सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 268 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, रविवार 12 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

नगरीय प्रशासन विभाग में 122 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले

रायपुर। राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 122 अधिकारियों-कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना की है। इनमें 66 अभियंता और 56 विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं। स्थानांतरित अधिकारियों-कर्मचारियों में कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता, प्रोग्रामर, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक से लेकर सहायक कार्यालय अधीक्षक, तकनीकी सहायक, लेखपाल, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, डॉटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक राजस्व निरीक्षक, समयपाल, कैशियर, वाहन चालक, चौकीदार, पंप अटेंडेंट और भृत्य शामिल हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्थानांतरित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वर्तमान स्थान से वेतन आहरित नहीं होगा।

बिलासपुर में स्टेशन के पास मालगाड़ी का वैगन बेपटरी

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में शनिवार को एक बार फिर रेल हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन के पास शंकर नगर आरओबी के नीचे डाउन लाइन पर चल रही मालगाड़ी का एक वैगन अचानक बेपटरी हो गया। घटना के बाद इंजीनियरिंग और ऑपरेशन विभाग की टीम ने सुधार कार्य किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी धीमी रफ्तार से गुजर रही थी। जिस कारण बड़ा हादसा टल गया। वैगन के पटरी से उतरते ही रेलवे ने तत्काल प्रभावित ट्रैक को सुरक्षित कर ट्रैफिक बहाली का काम शुरू कर दिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना का असर ट्रेनों की आवाजाही पर सीमित रहा। कुछ ट्रेनों का संचालन एहतियात के तौर पर धीमी गति से कराया गया, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए रेल यातायात को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की गई।

छत्तीसगढ़ में मानसून रूठा, धीमी पड़ी चाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखने को मिला। जहां कई जगह अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रविवार को सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर इन 4 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार जुलाई के दूसरे सप्ताह कमजोर पड़ गई है।यही वजह है कि 1 जून से 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में औसत से 21 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है।

छत्तीसगढ़ बन रहा देश का नया रेल व लॉजिस्टिक हब 51 हजार करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर हो रहा काम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास अब केवल नई रेल लाइनों के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, रोजगार, व्यापार और क्षेत्रीय संतुलित विकास का सबसे सशक्त आधार बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से पिछले ढाई वर्षों में रेलवे अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। वर्तमान में प्रदेश में 51 हजार करोड़ से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा रेलवे निवेश है और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला बन रहा है।

रिकॉर्ड बजटीय निवेश, नई रेल लाइनों का निर्माण, मल्टी-ट्रैकिंग, दोहरीकरण, आधुनिक स्टेशन, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण तथा दूरस्थ आदिवासी अंचलों तक रेल संपर्क के विस्तार ने छत्तीसगढ़ को देश के रेलवे मानचित्र पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। रेलवे क्षेत्र में हुआ रिकॉर्ड निवेश इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ष 2014 से पहले छत्तीसगढ़ को रेल परियोजनाओं के लिए औसतन लगभग ?300 करोड़ का वार्षिक बजट प्राप्त होता था, जबकि वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर ?7,470 करोड़ तक पहुंच गया है। अर्थात एक दशक में रेलवे बजट में लगभग 24 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह केवल बजट में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की विकास प्राथमिकताओं और राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता का परिचायक है।

छत्तीसगढ़ की रेल सुविधाओं के विकास में अभूतपूर्व गति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को अभूतपूर्व गति दी है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर जिस तेजी से नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है और उन पर कार्य प्रारंभ हुआ है, उसने प्रदेश के विकास की दिशा ही बदल दी है।

छत्तीसगढ़ मध्य भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य और मध्य भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र है। ऐसे में मजबूत रेल नेटवर्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। रेलवे विकास से उद्योगों की परिवहन लागत कम होगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

रावघाट रेल परियोजना विकास की नई धुरी बनकर उभरी

बस्तर अंचल में रावघाट रेल परियोजना विकास की नई धुरी बनकर उभरी है। दल्लीराजहरा से अंतागढ़ तक 77 किलोमीटर रेलखंड पर यात्री रेल सेवा प्रारंभ होने से हजारों ग्रामीण पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। परियोजना के अगले चरण में तुमापाल (ताहोकी) से कोसरोण्डा तक पुल-पुलियों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

अंतिम चरण में कोसरोण्डा से रावघाट तक रेलवे अधोसंरचना

कोसरोण्डा से रावघाट तक रेलवे अधोसंरचना का निर्माण भी अंतिम चरण में है। परियोजना पूर्ण होने पर रावघाट की लौह अयस्क खदानें सीधे भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ जाएंगी, जिससे उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को नई मजबूती मिलेगी। वहीं कोत्तावलसा-किरंदुल रेल लाइन के दोहरीकरण से बस्तर क्षेत्र में माल एवं यात्री परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रत्येक क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ना है। बस्तर, सरगुजा, जशपुर और अन्य दूरस्थ अंचलों में रेलवे पहुंचने से विकास का दायरा और व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे अब केवल यात्रियों और माल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन बन चुकी है। विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी रेल एवं लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस विज़न को साकार करने की दिशा में प्रदेश में अनेक महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का हो रहा पुनर्विकास

यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का लगभग 1,680 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। आधुनिक स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, मेमू सेवाओं का विस्तार तथा रायपुर में विकसित की जा रही आधुनिक रेल परिचालन सुविधाएं प्रदेश की रेलवे व्यवस्था को नई पहचान दे रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को भी 755 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इससे एसईसीएल और एमसीएल की खदानों से कोयले के परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा देश के ताप विद्युत संयंत्रों तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

रेल नेटवर्क के विस्तार में उल्लेखनीय उपलब्धियां

रेल नेटवर्क के विस्तार में भी छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 1853 से 2014 तक लगभग 161 वर्षों में जहां राज्य में करीब 1,100 रूट किलोमीटर रेल नेटवर्क विकसित हुआ था, वहीं अब छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क 2,200 रूट किलोमीटर से अधिक करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। लगभग 1,200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक, शत-प्रतिशत रेल विद्युतीकरण, अत्याधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था तथा मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं ने रेलवे परिचालन को अधिक सुरक्षित, तेज और ऊर्जा दक्ष बनाया है।

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नए रेल कॉरीडोर का निर्माण

प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल खरसिया-नवा रायपुर-परमालकसा रेल कॉरिडोर को 8,741 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। 278 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर कोलकाता-मुंबई रेल मार्ग का प्रभावी विकल्प बनेगा। इससे प्रदेश की लॉजिस्टिक्स लागत में प्रतिवर्ष लगभग 2,520 करोड़ की कमी आने का अनुमान है, अतिरिक्त माल परिवहन क्षमता विकसित होगी तथा उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल लाइन, कोरबा अंबिकापुर, गढ़चिरौली-बीजापुर बचेली, रावघाट-जगदलपुर, अंबिकापुर-बरवाडीह, धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा, गेवरा-पेंड्रा, खरसिया-धरमजयगढ़ तथा बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन जैसी परियोजनाएं प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रही हैं। धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजना जशपुर जिले को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।

मेंटेनेंस के कारण 14 से 24 जुलाई तक बंद रहेगा खुर्सीपार का रेलवे फाटक

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। मेंटेनेंस के लिए खुर्सीपार रेलवे फाटक को लोगों के आने जाने के लिए 14 से 24 जुलाई तक बंद किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार 14 को सुबह 8 से 24 की रात 8 बजे तक रखा जाएगा। इस दौरान रेलवे फाटक से किसी भी तरह के वाहनों के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। इस गेट के बंद होने की वजह खुर्सीपार, डबरापारा, जामुल, ट्रांसपोर्ट नगर, हथखोज, भिलाई-3, चरोदा, पुरैना, सिरसा-कला, गनियारी, मोरिद, सोमनी, पचपेड़ी समेत आसपास के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले डेढ़ लाख से अधिक लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। उनके लिए पटरी पार करने के लिए सिर्फ चरोदा जी-केबिन या फिर पावर हाउस अंडरब्रिज ही विकल्प होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन दिनों मेंटेनेंस के लिए सिरसा गेट अंडरब्रिज को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पहले से चंद्रा-मौर्या और रायपुर नाका अंडरब्रिज को मेंटेनेंस के लिए बंद रखा गया है। रेलवे अफसरों का कहना है कि मेंटेनेंस के दौरान इस बार मिडिल लाइन में काम किया जाएगा। मशीन से ट्रैक में बिछी गिट्टियों की छनाई की जाएगी। करीब ढाई फीट से अधिक गहरा करके काम किया जाएगा। इसकी वजह से इसमें समय लगेगा।

मेंटेनेंस के दौरान ट्रेनों की गति भी होगी नियंत्रित

मेंटेनेंस के दौरान खुर्सीपार गेट से गुजरने वाली ट्रेनों की गति नियंत्रित होगी। मेंटेनेंस के दौरान यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की गति अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे होगी। आमतौर पर ट्रेनों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। अफसरों का कहना है कि एक साथ सभी ट्रैक का मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है। इसकी वजह से बारी-बारी से एक-एक ट्रैक का मेंटेनेंस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में डाउन लाइन यानी दुर्ग से भिलाई वाले ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाएगा।

रायपुर के जेएनएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 20 सीटें बढ़ीं

■ 250 सीटों पर होगा दाखिला, स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission – NMC) के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (जेएनएम) मेडिकल कॉलेज, रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह कॉलेज पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ से संबद्ध है। ब्लॉक की ओर से 10 जुलाई 2026 को जारी अनुमति पत्र (Letter of Permission) के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है, यानी कुल 20 नई सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 1963 में 60 एमबीबीएस सीटों के साथ स्थापित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ने समय-समय पर अपनी प्रवेश क्षमता

में उल्लेखनीय वृद्धि की है। प्रारंभिक 60 सीटों से बढ़कर यह संख्या 100, वर्ष 2009 में 150, वर्ष 2019 में 180, वर्ष 2023 में 230 तथा अब एनएमसी की नवीनतम स्वीकृति के पश्चात 250 सीटों तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीटों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और वे अपने ही राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रयासों के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।

कोंडागांव में बड़ा हादसा

बस-कार की टक्कर में ड्राइवर की मौत

कोंडागांव। कोंडागांव जिले में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। जगदलपुर से रायपुर जा रही कांकेर रोडवेज की तेज रफ्तार यात्री बस ने घोड़ा गांव के पास कार को टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित बस सड़क किनारे जंगल में जा घुसी। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सभी कोंडागांव से गीदम जा रहे थे। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस तेज गति से चल रही थी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

संपादकीय

सरकारी से मोहभंग

निजी स्कूलों का सम्मोहन फिक्र की बात

तमाम विसंगतियों, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होना तथा समय के साथ कदमताल न कर पाने वाले सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोहभंग होना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देशभर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, छात्रों के प्रवेश व शिक्षकों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले केंद्र के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि छात्र सरकारी स्कूलों के विमुख हो रहे हैं और लगातार निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते दो सालों में लगभग 86 लाख छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं इसी दौरान प्राइवेट तथा बिना सरकारी मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख नए छात्र शामिल हुए हैं। 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' के अनुसार शुरुआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल 2023-24 के 24.8 करोड़ से घटकर साल 2025-26 में 24.72 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर 12.75 करोड़ से 11.89 करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादतर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं। यह हकीकत है कि जमीनी स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं दूसरी ओर शून्य दाखिले वाले स्कूलों की संख्या 12,954 से घटकर 5,663 हो गई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1.11 लाख से घटकर 1.01 लाख हो गई है।

"'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' के अनुसार शुरुआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल 2023-24 के 24.8 करोड़ से घटकर साल 2025-26 में 24.72 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर 12.75 करोड़ से 11.89 करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादतर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं।

दूसरी तरफ अब शिक्षकों की कुल संख्या 1.03 करोड़ है, जिसके चलते छात्र-शिक्षक अनुपात 25 से घटकर 24 हो गया है। वहीं लड़कियों की भागीदारी भी बढ़कर 48.4 होना उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिये संरचनात्मक सुविधाएं, छात्राओं के लिये शौचालय, हाथ धोने तथा पीने के पानी की व्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुआ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर दावों की हकीकत तार्किक कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सही मायने में किसी सुविधा का उपलब्ध होना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन देश के नीति-नियंताओं को समझना चाहिए कि समाज में जिस वर्ग को शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, वही सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी अपनी मजबूरी के चलते सरकारी स्कूलों की ओर रुख करता है। इसके बावजूद कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गाहे-बगाहे सवाल उठाए जाते रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हर बच्चे को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने को कहा था तो आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में शिक्षा के ये लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किए गए? यदि तब केंद्र व राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये ईमानदार प्रयास किए होते और पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये होते तो आज लोगों को सरकारी स्कूलों से मोहभंग न हो रहा होता। यदि संपन्न वर्ग, अधिकारियों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते तो शिक्षा जगत में आज व्याप्त गहरी विसंगति की खाई दूर हो जाती। हमारे तंत्र द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति उदासीनता दिखाने, शिक्षकों को गाहे-बगाहे गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने और समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति न करने से स्थितियां विकट हुई हैं। यह विडंबना ही कही जाएगी कि सत्तर के दशक में शिक्षा के उन्नयन के लिये गठित कोठारी आयोग की वह सिफारिश आज भी धूल फांक रही है, जिसमें शिक्षा पर देश के जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया था। आर्थिक तंगी से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता व साख पर आंच आई है।

विरोध करना जनतंत्र की सार्थकता की पहली शर्त

विश्वनाथ सचदेव

नागरिक का दायित्व और सरकार का कर्तव्य मिलकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को सार्थक बना सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, उसके अधिकारों का हनन नहीं।

शासन भले ही कोई भी चला रहा हो, पर जनतंत्र में असली शासक जनता ही होती है। जनता ही अपने वोट से शासन चलाने का अधिकार देती है या कहना चाहिए अवसर देती है। अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र को परिभाषित करते हुए जनतांत्रिक सरकार को 'जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा' बताया था। ऐसे में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से इतनी अपेक्षा तो की ही जानी चाहिए कि वे अपने असली शासक को उचित सम्मान देंगे। जनता को अपने शासकों से यह पूछने का अधिकार है कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं और यदि ऐसा लगता है कि चुनी हुई सरकार कुछ ग़लत कर रही है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार जनता को है। सच कहें तो इस तरह की निगरानी रखना जनता का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित शासक राजा नहीं होता, और न ही जनता प्रजा होती है।

जनता का यही अधिकार और कर्तव्य उसे चौकीदार की भूमिका निभाने का दायित्व भी देता है। इस चौकीदार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी चुनी हुई सरकार के काम-काज पर नजर रखेगा और यदि कुछ ग़लत हो रहा है तो न केवल उसे उजागर करेगा, बल्कि ग़लत के खिलाफ आवाज़ भी उठायेगा विरोध करना, ग़लत के खिलाफ प्रदर्शन करना हर जागरूक नागरिक का अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा जनतांत्रिक व्यवस्था में जुड़ी सभी संस्थाओं, जिसमें पुलिस प्रमुख है, का कर्तव्य है। पर जब निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं को राजा समझने लगे और पुलिस यह समझने लगे कि वह जनता की नहीं, सरकार की सेवक है तो इसे जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के प्रतिकूल ही माना जायेगा। लेकिन, क्या ऐसा होता है? दुर्भाग्य से इस प्रश्न का उत्तर नकारहाल ही में यह सवाल मुंबई उच्च न्यायालय के एक कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश ने उठाया था और स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 'नागरिकों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सेवक समझना किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता।' न्यायमूर्ति माधव जामदार एक नागरिक को तड़ीपार किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाले मामले में टिप्पणी कर रहे थे। नागरिक का अपराध यह था कि उसने सरकार के काम की आलोचना की थी, सरकारी आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया था। न्यायमूर्ति ने पुलिस की इस कार्रवाई की तीव्र आलोचना करते हुए जनतंत्र में नागरिक के अधिकारों का हवाला दिया और कड़े शब्दों में कहा, 'यह क्या चल रहा है, सारे नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है... ताकि वे विरोध-प्रदर्शन भी न कर सकें!'

जनतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक के पास सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर हथियार यही विरोध-प्रदर्शन करना है और उम्मीद की जाती है कि व्यवस्था नागरिक के इस अधिकार के प्रति सम्मान का भाव रखेगी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को यह अहसास करा दिया था कि आने वाले भारत में नागरिक के पास यही एक कारगर हथियार होगा। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी के इस अधिकार को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। सरकार की रीति-नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाना नागरिक का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। जब कोई सरकार नागरिक के इस अधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है तो वह लोकतंत्र को सीमित करने की ही कोशिश समझी जानी चाहिए।

इन दिनों देश में 'कॉकरोच पार्टी' का आंदोलन चल रहा है। राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर देश के युवा अपनी मांगों के समर्थन में पिछले एक पखवाड़े से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में शिक्षा मंत्री को दोषी मानते हैं और इसीलिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। युवाओं के इस आंदोलन में जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति लगातार सजग रहने वाले योगेंद्र यादव भी कॉकरोच पार्टी के इस प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे थे।

अपने भाषण में उन्होंने लगभग पंद्रह साल पहले इसी जगह हुए भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन का हवाला देते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि तब भी शुरुआती दौर में आंदोलनकारियों की संख्या तो लगभग आज जैसी ही थी, पर तब जंतर मंतर का यह प्रदर्शन स्थल इतना छोटा नहीं था। उन्होंने कहा, 'जंतर-मंतर अब छोटा हो गया है' और यह छोटा होना एक मैदान का क्षेत्रफल कम होना नहीं है, 'हमारा लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है।' हमारे लोकतंत्र के सिकुड़ने की यह बात हल्के में लिए जाने की बात नहीं है। सरकार की रीति-नीति पर नजर बनाये रखना और कुछ ग़लत लग रहा है तो उसका विरोध करना जनतंत्र की सार्थकता की पहली शर्त है। लोकतंत्र के सिकुड़ने का अर्थ है उन मूल्यों और आदर्शों का कमजोर पड़ना जो शासन-प्रणाली को अर्थवान बनाते हैं।

लोकतंत्र के सिकुड़ने का यह काम अनायास नहीं हो रहा, लोकतंत्र को संकुचित किया जा रहा है। दो तरीके हो सकते हैं ऐसा करने के पहले तो यह कि सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को बल प्रयोग करके कमजोर बनाया जाये और दूसरा ऐसे प्रदर्शन की उपेक्षा करके सत्ता के विरोधियों को हतोत्साहित किया जाये। सरकारें यह दोनों तरीके अपनाती हैं। पांच-छह साल पहले 2020-2021 में किसान आंदोलन को जिस तरह से दबाया गया था, वह देश ने देखा था। यह बात सही है कि तब लगभग एक साल तक चले इस आंदोलन के सामने सरकार को अंततः झुकना पड़ा था, पर जिस तरह किसानों को सरकार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था, वह भी किसी से छिपा नहीं रहा। सत्ताशीर्ष पर बैठे लोग चाहते तो अपने बंगले से निकलकर कुछ ही दूरी पर आंदोलन करते किसानों से मिलकर समस्या का समाधान आसानी से कर सकते थे, पर उन्होंने कुल मिलाकर आंदोलनकारियों को थका देने की नीति अपनायी थी। सरकार का यह रवैया किसी भी दृष्टि से जनतांत्रिक मूल्यों-मर्यादाओं के अनुकूल नहीं था।

बहरहाल, हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पुराना लोकतंत्र भी कहते हैं हम अपने भारत को। सबसे बड़ा या सबसे पुराना होना हमारी विशेषता हो सकती है, पर इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि हमारे लोकतंत्र में कोई कमी नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का यह कहना कि देश के नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है और विवेकशील नागरिकों की यह समझ कि हमारा लोकतंत्र छोटा होता जा रहा है, हमें यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हम कितने सावधान हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कसौटी है और सरकार की ग़लत लगने वाली नीति का विरोध करना एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की जागरूकता का प्रमाण है। हर पांच साल बाद चुनाव होना ही पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तकाज़ा है कि नागरिकों की जागरूकता सक्रिय भूमिका निभाती दिखे।

नागरिक अपने वोट से सरकार बनाते हैं, इसलिए उनका यह दायित्व बनता है कि वह अपने बनायी सरकार पर नज़र रखें। और सरकार का भी यह दायित्व है कि नागरिक के अधिकारों पर अंकुश लगाने का निरर्थक प्रयास न करे। नागरिक का दायित्व और सरकार का कर्तव्य मिलकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को सार्थक बना सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, उसके अधिकारों का हनन नहीं।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

विधिक बिरादरी के लिए 'वेकअप कॉल'

डॉ. सुधीर कुमार

'नेशनल लीगल एकेडमी' का उद्देश्य केवल वकीलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से 'सक्षम वकीलों की फौज' में बदलना है। यह एकेडमी नए वकीलों के लिए एक 'मेंटरशिप हब' के रूप में कार्य करेगी, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अपने व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे।

कानून स्थिर नहीं है, यह जीवित है और समय के साथ बदलता रहता है। एक वकील के लिए उसकी डिग्री केवल एक प्रवेश द्वार है, लेकिन असली परीक्षा अदालत के फर्श पर हर दिन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'अजय विज बनाम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' (2026) मामले में जो टिप्पणी की, वह महज एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि भारतीय विधिक बिरादरी के लिए एक अत्यंत गंभीर 'वेकअप कॉल' है।

यह मामला केवल एक वकील का निजी विवाद नहीं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की एक गंभीर खामी को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। एक वकील की कानूनी राय को 'लापरवाही' मानकर उसे 'कॉशन लिस्ट' में डालना, वकील की बदलती भूमिका और उसकी व्यावसायिक जवाबदेही पर बड़े प्रश्नचिह्न लगाता है। यह निर्णय बताता है कि वकील अब केवल अपने मुवक्किल का पक्ष रखने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है, बल्कि वह एक 'विशेषज्ञ' बन गया है, जिसकी एक छोटी-सी गलती भी पूरी न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल खड़ा कर सकती है।

आज के डिजिटल युग में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलता वैश्विक परिदृश्य कानून के स्वरूप को निरंतर नया आकार दे रहे हैं, क्या केवल पुरानी किताबों के ज्ञान से न्याय की रक्षा संभव है? सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि वकीलों के लिए 'कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन' अनिवार्य हो और एक 'नेशनल लीगल एकेडमी' की स्थापना की जाए, भारतीय न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक साहसी और दूरदर्शी कदम है।

कानून का पेशा केवल बहस करना नहीं है, बल्कि यह एक 'पवित्र विश्वास' है, जिसे बनाए रखने के लिए निरंतर विकास अनिवार्य है। आज के इस 'ज्ञान युग' में, कानूनों, तकनीक और विनियामक ढांचों में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि वर्षों पहले अर्जित किया गया ज्ञान आज पूरी तरह अप्रासंगिक हो सकता है। इसके साथ ही, कानूनी क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे दूर करना समय की मांग है।

आज के आधुनिक वकील के लिए ई-कोर्ट्स, वर्चुअल हियरिंग, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट और कानूनी डेटा विश्लेषण में दक्ष होना केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आवश्यकता है। इसके अलावा, अदालती शिष्टाचार, मुवक्किल के प्रति जवाबदेही और अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर नैतिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस पेशे की गरिमा हमेशा बनी रहे।

अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में 'मैन्डेटरी कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन' लागू है। वहां वकीलों के लिए अपने लाइसेंस को बनाए रखने हेतु हर साल निश्चित घंटों की कानूनी शिक्षा या सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य होता है। इसी तरह, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में बार एसोसिएशन और सरकार के सहयोग से 'निरंतर पेशेवर विकास' कार्यक्रमों को कड़ाई से लागू किया जाता है, जहां इन क्रेडिट्स को पूरा न करने पर वकील के अभ्यास करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित तक किया जा सकता है।

भारत में कानूनी पेशे का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन गुणवत्ता उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी है। आज देश में वकीलों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है और हर वर्ष हजारों युवा कानून की डिग्री लेकर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरी ओर, भारतीय अदालतों में लंबित मामलों का बोझ 5 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। वकीलों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति 'प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट' के अवसर सीमित हो गए हैं।

'नेशनल लीगल एकेडमी' का उद्देश्य केवल वकीलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से 'सक्षम वकीलों की फौज' में बदलना है। यह एकेडमी नए वकीलों के लिए एक 'मेंटरशिप हब' के रूप में कार्य करेगी, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अपने व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे। इस प्रयास से किताबी ज्ञान और अदालती हकीकत के बीच की खाई मिटेगी और मुकदमों के जल्द निस्तारण की दर में 15 से 20 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हो सकेगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी पेशे के मानकों को ऊंचा उठाने के लिए एक 'सुपर-रेगुलेटर' के रूप में अपनी भूमिका को सशक्त बनाना होगा। इसके कार्यान्वयन हेतु सबसे पहले वकीलों के लिए एक अनिवार्य क्रेडिट-आधारित प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसके तहत हर वकील के लिए प्रतिवर्ष 20 से 30 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो। इस शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए एक हाइब्रिड लर्निंग मॉडल अपनाना आवश्यक है, जहां नेशनल लीगल एकेडमी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जोड़कर दूरदराज के क्षेत्रों के वकीलों तक पहुंचाया जा सके।

एकेडमी की सफलता के लिए 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' का मॉडल सबसे प्रभावी होगा। इसमें शीर्ष लॉ फर्मों और अनुभवी वकीलों को 'गेस्ट लेक्चरर' के रूप में जोड़कर व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सकता है। न्यायिक प्रणाली में 'नेशनल लीगल एकेडमी' की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कानूनी पेशे को केवल 'पढ़ाई' तक सीमित न रखकर इसे एक 'थिंक टैंक' में बदल सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसे अधिकारों के हनन के बजाय 'अधिकारों के विस्तार' के रूप में देखना चाहिए।

लेखक कुरुक्षेत्र वि.वि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

विशेषज्ञों का अध्ययन दूर करेगा इथेनॉल के भ्रम

दिनेश सी शर्मा

अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से कारों की ईंधन दक्षता कम होती है तो इससे आर्थिक लागत बढ़ेगी। कृषि-खाद्य विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि इथेनॉल मिश्रण से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। किसान खाद्य फसलों के बजाय ज़्यादा पानी खर्च करने वाली गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहे हैं।

इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को तेज़ी से बढ़ावा देने की सरकारी नीति हाल के हफ़्तों में लोगों की कड़ी आलोचना का निशाना है, हालांकि, यह नीति 2022 से लागू है। 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का मूल लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन समयपूर्व 2025 कर दिया गया।

इस नीति के फायदों के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं—ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत से लेकर किसानों के कल्याण तक। फिर भी, वाहन मालिक इंजन खराब होने और माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं। अपने बचाव में, सरकार का कहना है कि यह नीति सबूतों पर आधारित है और डेटा समर्थित है, जिसमें अधिकांशतः पेट्रोलियम संगठनों के बेनामी और अप्रकाशित अध्ययनों का हवाला दिया गया है।

वाहनों पर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के असर के दावों को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र अथवा विशेषज्ञों द्वारा जांचा-परखा अध्ययन मौजूद नहीं है। अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाली कारों की फ़्यूल एफ़िशिएंसी (ईंधन दक्षता) कम है—जैसा कि अब कार निर्माता भी मान रहे हैं—और इंजन खराब हो रहे हैं—जैसा कि वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं—तो इससे आर्थिक लागत बढ़ेगी। इसके अलावा, कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इथेनॉल मिश्रण से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि किसान खाद्य फसलों के बजाय ज़्यादा पानी खर्च करने वाली गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इथेनॉल की बढ़ती मांग के मद्देनजर निर्माता कंपनियां मक्का और चावल का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर कर रही हैं। सरकार को नीति के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना जरूरी है और इसके फायदों के बारे में ठोस सबूत पेश करने चाहिए, न कि आलोचकों पर गलत इरादे का आरोप मढ़ देना या इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर लोगों के गुस्से को नज़रअंदाज़ करना।

लोग अक्सर ब्राज़ील का उदाहरण देते हैं, जहां 1980 के दशक में इथेनॉल मिश्रण शुरू किया गया था। इसके दीर्घकालीन असर अब जाकर सामने आ रहे हैं। यह नीति 1970 के दशक में चीनी के फालतू उत्पादन का सीधा नतीजा थी और इसे चीनी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया था। पिछले चार दशकों में, इसने वहां ज़मीन के इस्तेमाल में भारी बदलाव किया है, नतीजतन, ईंधन फसलों के लिए जगह बनाने के वास्ते अमेज़न के जंगलों की कटाई के कारण भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। वैसे भी, बड़े पैमाने पर ऊर्जा फसलो की खेती के लिए भारत की जलवायु और मिट्टी की स्थिति ब्राज़ील जैसी नहीं है। किसी भी नई तकनीक की तरह, ग्रीन तकनीक

को भी— चाहे वह इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियां—व्यापक पैमाने पर लागू करने पर अनचाहे बुरे असर हो सकते हैं। जैसे किसी नई वैक्सीन या दवा को लाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, वैसे ही सभी नई तकनीकों का अलग-अलग स्थितियों में कुछ समय तक फील्ड-टेस्ट किया जाना चाहिए, और उससे मिले डेटा का विश्लेषण करवाने को स्वतंत्र विशेषज्ञों को दिया जाए।

परिवहन अर्थव्यवस्था का एक अहम अंग है, और किसी भी नई तकनीक को लागू करने से पहले उसकी कई पहलुओं से जांच होनी चाहिए और सिर्फ़ वाहन निर्माता ही नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के साथ उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह काफी चौंकाने वाली बात है कि सरकार ने अपने बचाव में वाहन निर्माता कंपनियों को उन शिकायतों का जवाब देने के लिए बुलाया—जो वाहन का उपयोग करने वाले कह रहे हैं—जैसे कि माइलेज में कमी और गाड़ियों के धातु एवं रबर पुर्जों का खराब होना। दुनिया भर में वाहन निर्माता डेटा में हेरफेर करने के लिए कुख्यात हैं, जैसा कि 2015 में अमेरिका में फॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल में यह सामने आया था। कार बनाने वाली इस कंपनी ने अपनी कारों के डीज़ल इंजन को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया था कि टेस्टिंग के दौरान उत्सर्जन सीमा नियंत्रण में दिखे ताकि नियामक मानकों पर खरा उतरता दिखाई दे; नतीजतन, 40 गुना ज़्यादा प्रदूषण पैदा करने वाली कारों को भी मानकों के भीतर पाया मानकर स्वीकृति दे दी गई।

अगर पेट्रोलियम मंत्री के दावे के मुताबिक इथेनॉल नीति वाकई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो सरकार को उन तमाम अध्ययनों के नतीजे सार्वजनिक करने चाहिए, जो ईंधन की क्षमता, अलग-अलग पुर्जों और इंजन पर मिश्रित ईंधन के दीर्घकालीन प्रभाव और अलग-अलग तरह की गाड़ियों पर अलग-अलग परिचालन स्थितियों में परीक्षण डेटा को जांचने के लिए किए गए हों। इसके अलावा, हमें इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में वैज्ञानिक सुबूत चाहिए, जो कि इथेनॉल के संपूर्ण पर्यावरणीय एवं कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित हो — यानी कच्चे ईंधन के उत्पादन से लेकर कारों में वास्तविक इस्तेमाल होने तक। फिर, हमें मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल करने पर लागत-लाभ विश्लेषण की ज़रूरत है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइलेज गिरने की चिंताएं हैं। अगर माइलेज 5 प्रतिशत भी कम हो जाती है और कार उपयोग करने वालों को ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ता जाए, तो आर्थिक फ़ायदों और विदेशी मुद्रा की बचत के दावे हवा हो जाते हैं।

दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी के मामले में भी ऐसी ही बातें लागू होती हैं। यह पॉलिसी मुख्यतः दुपहिया और तिपहिया केंद्रित है। इसमें पेट्रोल से चलने वाली नई मोटरसाइकिलों और आटो-रिक्शा के पंजीकरण को बंद करने की समय-सीमा तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री के दावे में इस कदम को सही ठहराने के लिए चुनिंदा डेटा का सहारा लिया है।

दरअसल, दिल्ली में कुल गाड़ियों में दुपहिया का अंश 62 फीसदी है, लेकिन वाहन चालन से पैदा होने वाले पाटिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) उत्सर्जन में उनका अंश मात्र 15 प्रतिशत है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, बेंगलुरु के गुफरान बेग द्वारा प्रकाशित 2025 नीति सारांश अनुसार, हल्के और भारी व्यावसायिक वाहनों का अंश परिवहन उत्सर्जन में 39 प्रतिशत है, जबकि शहर की कुल गाड़ियों में उनकी हिस्सेदारी 3 फीसदी से भी कम है। अतः व्यावसायिक वाहनों और बसों से पैदा होने वाले उत्सर्जन को कम करने से पर्यावरण और इंसानी सेहत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सार्वजनिक नीतियों में तथ्य आधारित क्रमबद्ध व्यवस्था का होना जरूरी होता है।

पर्यावरण पर संसदीय स्थायी समिति ने नीति के टुकड़ों में बंटे हुए नज़रिए के खिलाफ चेताया था और सुझाव दिया था कि राज्य स्तर के बजाय एयरशेड स्तर पर उपाय किए जाएं। अगर ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया, तो दिल्ली में ईवी अपनाने से पर्यावरण को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए; क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले वाहन पड़ोसी राज्यों में चले जाएंगे और वहां से आने वाली साझा हवा में प्रदूषण बढ़ाते रहेंगे।

सार्वजनिक हित नीति बनाने का काम भरोसेमंद और प्रासंगिक प्रमाण आधारित हो, न कि राय, अल्पकालिक लाभ, संकीर्ण राजनीतिक और कारोबारी हितों या विचारधारा पर। नीति से जुड़े फ़ैसले पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए और उनका एकमात्र मकसद जनहित हो।

लेखक विज्ञान संबंधी विषयों के विशेषज्ञ हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाऐं
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

भिलाई में 17 अगस्त से फिर गूंजेगी शिवमहापुराण कथा

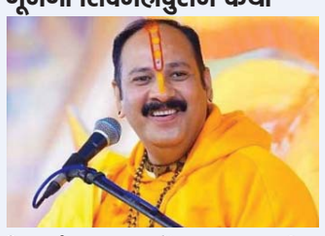

भिलाई। सावन में एक बार फिर भिलाई शिवमय होने जा रहा है। सीहोर वाले पं. प्रदीप मिश्रा की सात दिवसीय शिव महापुराण कथा 17 अगस्त नाग पंचमी सोमवार से होगी, जो 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई में चलेगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होगी। सात दिनों तक भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण के बीच भगवान शिव की महिमा गाई जाएगी। इसमें प्रदेश सहित देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के प्रमुख दया सिंह ने बताया कि लगातार तीसरे वर्ष शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। इसे इस बार गोल्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। कथा से एक दिन पहले 16 अगस्त रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत सेक्टर-5 स्थित गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ होगी। हजारों श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण करेंगी। इसमें आकर्षक, मनमोहक धार्मिक झांकियां, भजन, कीर्तन और शिव भक्ति की अनुपम छटा देखने को मिलेगी। कथा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जाएंगी। कथा स्थल पर पीने का पानी, बैठक, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं रहेंगी।

महादान अंगदान का संकल्प, मातृशक्तियों का सर्वधर्म सेवा संस्था ने किया सम्मान

भिलाई। सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा भिलाई निवास में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन कर समाज में मानवता, सेवा और अंगदान के प्रति जागरूकता का प्रेरणादायी संदेश दिया गया। इस अवसर पर साधना मौर्य, वैशाली कालमेघ एवं किरण प्रभा मन्ने को महादान अंगदान का संकल्प लेने पर संस्था की ओर से पुष्पहार, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि अंगदान जीवन के बाद भी मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। इन तीनों मातृशक्तियों का यह संकल्प समाज के लिए प्रेरणास्रोत है और निश्चित रूप से अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए आगे आने की प्रेरणा देगा। कार्यक्रम के दौरान किरण प्रभा मन्ने ने जरूरतमंद मरीजों की सुविधा हेतु एक नई व्हीलचेयर सर्वधर्म सेवा संस्था को भेंट की। संस्था ने इस मानवीय सहयोग के लिए उनका विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्हीलचेयर जरूरतमंदों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर परमिंदर सिंह ग्रेवाल पूर्व महासचिव, प्रतीक भोई संस्थापक, राकेश रत्नाकर महासचिव, गायत्री गोस्वामी, निर्मला, ज्योति भोई, रत्नाकर, सुधा शर्मा, जया सरनाइक, उषा कसेर, मुरली कृष्ण, मनमोहन सिंह एवं जय प्रकाश सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

भिलाई विद्यालय में शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए पालक शिक्षक समिति का गठन

भुवनेश्वरी देवांगन बनी अध्यक्ष, के मोहन राव व रीना देवी चुने गए उपाध्यक्ष

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेक्टर-2 स्थित भिलाई विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए पालक शिक्षक समिति का गठन किया गया। कक्षा 9वीं ,10वीं एवं 11वीं में उच्चतम अंक पाने वाली छात्राओं प्रेरणा देवांगन, के हारिका एवं रिया राजभर के पालकों भुवनेश्वरी देवांगन, के मोहन राव व रीना देवी को विद्यालय द्वारा पालक शिक्षक समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया द्य सभागार में उपस्थित पालकों में से 3 सदस्यों डॉ.सुधाकर सिंह, प्रदीप मान्डिया, नीतू दुबे का चयन निर्वाचन पद्धति से किया गया।

इसके बाद सभी सदस्यों ने मिलकर भुनेश्वरी देवांगन को प्रेसिडेंट तथा के मोहन राव व रीना देवी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया द्य पदेन सचिव विजय सिंह पवार प्राचार्य, कोषाध्यक्ष सरिता शाक्या, सहसचिव देवेन्द्र कुमार साहू, शिक्षक सदस्य पंच राम साहू, सतीश मिश्रा एवं सजिता राजेश चुने गए ।

इससे पहले संगीत शिक्षक सतीश मिश्रा और शैलेन्द्र भोई के मार्ग दर्शन में छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गयाद्य समिति की कोषाध्यक्ष सरिता कुमारी शाक्या ने गत वर्ष के आय व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। प्राचार्य विजय सिंह पवार ने गतवर्ष की उपलब्धियों का पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी, उन्होंने ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के तीन स्तंभों पालक-बालक-शिक्षक की आवश्यकता बताते हुए पालक शिक्षक समिति के सदस्यों से सहयोग की अपील की।

सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन सजिता राजेश एवं धन्यवाद ज्ञापन देवेन्द्र कुमार साहू के द्वारा प्रेषित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य विजय सिंह पवार, वरिष्ठ व्याख्याता सरिता कुमारी शाक्या, देवेन्द्र कुमार साहू, पवन कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार पुरेना, पंच राम साहू, वंदना सोनवाने, सुनीता अनिल, संगीता मिश्रा, गोवर्धन साहू, राजेश साहू, एस. एन. साहू, रजनी रजक, एस. के खोब्रागडे, एस. के. साहू, एमएम राव, विशाखा पांडे, भावना, फातेहीन मोईन, पूर्णिमा शर्मा, वाई मनीषा, प्रतिमा, मनीषा वर्मा का सहयोग रहा द्य इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के पालक उपस्थित थे।

विश्व जनसंख्या दिवस पर दुर्ग जिले में चला व्यापक विधिक जागरूकता अभियान

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के परिपालन में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला, कोलिहापुरी एवं पुलगांव उच्च माध्यमिक शाला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी विरेन्द्र सिंह, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी आरती ध्रुव एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी प्रियंका गोस्वामी तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के दो काउंसलर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

पुलगांव उच्च माध्यमिक शाला में आयोजित कार्यक्रम में न्यायाधीशों का विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने विद्यार्थियों को विश्व जनसंख्या दिवस के इतिहास, उद्देश्य एवं महत्व से अवगत कराया। इसके साथ ही कानून के प्रति जागरूकता, यातायात नियमों के पालन, कैरियर निर्माण तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी साझा करने के खतरों के बारे में भी जागरूक किया गया तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए गए।

शासकीय माध्यमिक शाला, कोलिहापुरी में आयोजित शिविर में LADCS के काउंसलरों ने विद्यार्थियों को विश्व जनसंख्या दिवस के महत्व, नशामुक्ति, गुड टच एवं बैड टच तथा बाल संरक्षण संबंधी कानूनों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, बिना हेलमेट एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने तथा साइबर अपराधों से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उपस्थित न्यायाधीशों एवं काउंसलरों ने सरल एवं प्रेरणादायक ढंग से उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष के विनोद कुजूर एवं सचिव उमेश कुमार भागवतकर के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी जागरूकता शिविर आयोजित कर नागरिकों को जनसंख्या संतुलन एवं उससे जुड़े सामाजिक विषयों के प्रति जागरूक किया गया।

समग्र रूप से यह अभियान विद्यार्थियों एवं आमजन में विधिक जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।

भाजपा युवा नेता तरुण परगनिहा को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

भिलाई। भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ की घोषित प्रदेश कार्यसमिति में तरुण परगनिहा को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोनीत किया गया है। इस नियुक्ति पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समाज के वरिष्ठजनों एवं शुभचिंतकों ने तरुण परगनिहा को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। तरुण परगनिहा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संयोजक तथा संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो विश्वास उन पर व्यक्त किया है, उस पर वे पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे संगठन को मजबूत बनाने, समाज सेवा और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पार्टी की रीति-नीति को जन-जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

ब्लास्ट फर्नेस-8 'महामाया' ने 21 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस-8 'महामाया' ने उत्पादन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 10 जुलाई 2026 को अपने अभियान (कैम्पेन) के दौरान 21 मिलियन टन संचयी हॉट मेटल उत्पादन का महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पार कर लिया।

2 फरवरी 2018 को कमीशन की गई ब्लास्ट फर्नेस-8 ने यह उपलब्धि मात्र 3,080 दिनों में हासिल कर भारतीय इस्पात उद्योग में एक नया मानदंड स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि फर्नेस ने 20 मिलियन टन से 21 मिलियन टन संचयी हॉट मेटल उत्पादन का सफर केवल 121 दिनों में पूरा किया, जो इसकी उत्कृष्ट परिचालन क्षमता, उच्च तकनीकी दक्षता तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है।

ब्लास्ट फर्नेस-8 'महामाया' भिलाई इस्पात संयंत्र के हॉट मेटल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस्पात निर्माण प्रक्रिया की समग्र दक्षता को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। अत्याधुनिक तकनीक, सुव्यवस्थित परिचालन, प्रभावी रखरखाव तथा सुरक्षित कार्य संस्कृति के बल पर विभाग लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नए उत्पादन मानदंड स्थापित कर रहा है।

इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर भिलाई इस्पात संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन ने ब्लास्ट फर्नेस-8 की पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके समर्पण, तकनीकी दक्षता एवं उत्कृष्ट टीमवर्क की सराहना की।

यातायात एवं डीज़ल विभाग में कर्म शिरोमणि पुरस्कार समारोह हुआ आयोजित, 12 कार्मिक सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के यातायात एवं डीज़ल (टी एंड डी) विभाग में दिनांक 10 जुलाई 2026 को विभागीय सभागार में कर्म शिरोमणि पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 12 कार्मिकों को कर्म शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक प्रभारी (टी एंड डी विभाग) गोपीनाथ मलिक ने चयनित कार्मिकों को स्मृति-चिन्ह, प्रशस्ति-पत्र तथा उनके जीवनसाथियों के लिए प्रशंसा-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यातायात एवं डीज़ल विभाग संयंत्र के परिचालन की महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सुरक्षा एवं अनुशासित कार्यप्रणाली सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनसे भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करते रहने तथा अपने सहकर्मियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर रतन कुमार त्रिपाठी, जरनैल सिंह, अजीत कुमार मंडल, राकेश कुमार सिंह, रविन्द्र चंद्राकर, पीलू राम वर्मा, नवनीत जॉन, उदय सिंह, दिलीप कुमार साहू, दुर्योधन सिंह, हेमचंद घृतलहरे एवं नारायण सिंह पैकरा को कर्म शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समारोह में टी एंड डी विभाग के महाप्रबंधक मनोज प्रसाद, उप महाप्रबंधक बी. डी. टुडू, सहायक महाप्रबंधक योगेश ठाकुर, एस. के. साहू, मोहम्मद ए. आर. शरीफतथा वरिष्ठ प्रबंधक श्रीधर नाग सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त कार्मिकों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य, सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एवं टीम भावना की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी समर्पण एवं लगन के साथ कार्य करते हुए अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम का स्वागत एवं संचालन सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन-सेवाएं) डॉ. उपेंद्र कुमार शर्मा ने किया। समारोह के सफल आयोजन में अफज़ल खान, सोमा रानी, लक्ष्मी दौलतानी एवं प्रिया ठाकुर का विशेष योगदान रहा।

नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन समारोह आयोजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के भिलाई विद्यालय, सेक्टर-2 में कक्षा 9 एवं 11 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली, शैक्षणिक वातावरण, उपलब्धियों तथा अनुशासन संबंधी व्यवस्थाओं से परिचित कराना था।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महाप्रबंधक (शिक्षा) शिखा दुबे थीं। इस अवसर पर शिक्षा विभाग से विभारानी कटियार, मनीष तिवारी, राजेश गुप्ता, वरिष्ठ व्याख्याता सरिता कुमारी शाक्य, देवेन्द्र कुमार साहू, मनोज कुमार पुरैना, पवन कुमार अग्रवाल एवं पंचराम साहू सहित नवप्रवेशी विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सतीश मिश्रा, शैलेन्द्र भोई, रजनी रजक एवं पी. मनीषा के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत एवं नृत्य से हुआ।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि शिखा दुबे ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में असीम संभावनाएँ होती हैं और उन्हें स्वयं को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करने, लक्ष्य का समय रहते निर्धारण करने तथा शिक्षकों से अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों का भिलाई विद्यालय परिवार में स्वागत करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर प्राचार्य विजय सिंह पवार ने स्वागत उद्बोधन एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विद्यालय की गत वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों, शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों तथा विद्यालय की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान गत वर्ष विभिन्न कक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपना परिचय दिया। कु. रिया, सुजैन, कु. कनिष्का शर्मा एवं कु. सुहानी पाढ़ी ने विद्यालय में अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिखा दुबे ने कक्षा 9 एवं 11 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले नवप्रवेशी विद्यार्थियों राजवीर कोल, अयान शेख, सृष्टि एवं यश केसरी को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों का विद्यालय के समस्त शिक्षकों से परिचय भी कराया गया। कार्यक्रम का संचालन सुनीता अनिल ने किया तथा सरिता कुमारी शाक्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में वंदना सोनवानी, सजिता राजेश, सत्य नारायण साहू, संगीता मिश्रा, डॉ. उपमा शुक्ला, गोवर्धन साहू, सुरेन्द्र कुमार खोब्रागड़े, सरवन कुमार साहू, मदन मोहन राव, विशाखा पांडे, भावना, पूर्णिमा शर्मा, नेहा सिंह एवं प्रतिमा का विशेष योगदान रहा।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जशपुर में विज्ञान शिक्षा को मिल रहा नवाचार का नया आयाम

रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यालयों में प्रयोग आधारित, गतिविधि आधारित एवं दक्षता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में जशपुर जिले में एक अभिनव पहल की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं इनोवेशन एंड साइंस प्रमोशन फाउंडेशन के सहयोग से स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय, जशपुर में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में पुणे से आए इनोवेशन एंड साइंस प्रमोशन फाउंडेशन के संस्थापक एवं वैज्ञानिक डॉ. प्रचेता मलिक तथा उनकी चार सदस्यीय टीम ने विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित प्रयोगों का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया। जशपुर जिले के सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विज्ञान विषय को अधिक रोचक, व्यावहारिक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

जैविक ईंधनों पर निर्भरता घटाने की दिशा में बालोद की अभिनव पहल

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन के विजन को साकार करने की दिशा में बालोद जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह पहल जैविक ईंधनों पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा जिले में ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय कार्यों में वाहनों की पूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 7.2 किलोवाट क्षमता का सार्वजनिक ईवी चार्जर स्थापित किया गया है।

सेवा सेतु पोर्टल से साकार हो रहा 'जनता के द्वार, डिजिटल सरकार' का संकल्प

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को नई गति मिल रही है। शासन की महत्वाकांक्षी पहल 'सेवा सेतु' पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं अब पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा सेतु के जरिए सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण होने से आम नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम एवं प्रभावी बन रही है। इसी दिशा में दुर्ग जिले में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राजपत्र (गजट) प्रकाशन सेवा के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन का एक उल्लेखनीय उदाहरण सामने आया है। नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण का निराकरण तय समय-सीमा के भीतर किया गया। इसके उपरांत आवेदक को सेवा सेतु के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र प्रकाशन उपलब्ध कराया गया।

उप मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित जिलों में विकास और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों, जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन एवं वकीलों का दल बनाकर प्रकरण वापसी पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह इसकी प्रगति की समीक्षा बैठक संबंधित प्रकरण से जुड़े जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाएगी। ऐसे नक्सल प्रकरण जिनमें जनहानि नहीं हुई है उनमें जेल में निरुद्ध नक्सल आरोपियों की रिहाई आवश्यक है। कभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए शासन द्वारा नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर ऐसे ग्रामों में 1-1 करोड़ रुपयों के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को आजीविका प्राप्त होने के साथ ग्रामों का विकास भी होगा। इसके लिए वर्तमान में 50 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। जिसमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 एवं नारायणपुर के 10 ग्राम शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त हुए गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारकों का निर्माण भी कराया जाए ताकि शहीदों एवं पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान मिल सके। उन्होंने जिलावार नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों एवं मृत नागरिकों के मामलों, उनके परिजनों को प्रदान की गई सहायता तथा लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को शासन की सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर विलंब न हो। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुनर्वास नीति का पालन करते हुए पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का अगले एक माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पीड़ितों एवं पुनर्वासितों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए तैयार डेश बोर्ड में जानकारी प्रविष्ट करने को कहा। उन्होंने माओवादियों द्वारा लुटे गए हथियारों की बरामदगी पर अंतर्राज्यीय समिति बनाकर मिलान करने एवं जंगल में कोई भी हथियार ना छूटे यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नारायणपुर में वन महोत्सव का भव्य आयोजन

वन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर हरियाली रथ को किया रवाना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के प्रसार को एक जन-आंदोलन का रूप देने के लिए नारायणपुर वनमण्डल के अंतर्गत पुलिस लाइन में वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप थे। इस विशेष अवसर पर जिले के अंतर्गत शहीद हुए 118 पुलिस जवानों के नाम पर एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत शहीद वाटिका में पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक संदेश दिया गया।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि शहीदों की याद में लगाया गया प्रत्येक पौधा उनके सर्वोच्च बलिदान को चिरस्थायी बनाए रखने का पावन प्रतीक है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण मिल सके।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने शहीद वाटिका में स्वयं पौधा रोपित कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया।

इस वाटिका में जैव विविधता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आम, अमलतास, रुद्राक्ष, आंवला, लक्ष्मणफल, अशोक, चीकू, लीची, रीठा, हल्दू, मुण्डी, गुलमोहर, साल, साजा, हर्रा, बेहड़ा, शीशम, खम्हार, बादाम, कटहल, अंजीर, युसींटा, शीशु, सेब, मालाबार नीम, बेल, मुनगा, मीठा नीम, सफेद चंदन, लाल चंदन, कनकचंपा, करंज, पीपल, सागौन, इंडियन रॉकवुड, नीम, रेन-ट्री, महुआ, एवोकाडो, रामफल, स्टारफ्रूट, कुसुम, मौसंबी, नींबू, कदंब, सिल्वर ओक, करौंदा, मोललाईट, मलबरी और सपोटा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण 118 प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है। किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत चयनित हितग्राहियों एवं किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से मूल्यवान सफेद चंदन और मिलिया डुबिया (मालाबार नीम) के पौधों का नि:शुल्क वितरण किया गया।

सुपगांव संयुक्त वन प्रबंधन समिति के 15 कर्मठ ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए उन्नत ग्राफ्टेड (कलमी) प्रजाति के आम, अमरूद, कटहल, जामुन, सिंदूरी और नींबू के पौधे प्रदान किए गए। सीडबॉल तकनीक का प्रयोग- स्कूली बच्चों द्वारा उत्साहपूर्वक निर्मित किए गए 'सीडबॉल' का वन क्षेत्रों में छिड़काव किया गया, जो आगामी वर्षा ऋतु में स्वत: अंकुरित होकर प्राकृतिक वनों को और समृद्ध बनाएंगे।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका परिषद नारायणपुर के अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनमण्डल नारायणपुर के समस्त अधिकारी-कर्मचारी तथा भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहकर इस हरित संकल्प के साक्षी बने।

हरियाली रथ और ट्री-एटीएम से बंटे 10 हजार पौधे

ग्रामीण अंचलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पौधों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री ने हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के ग्रामीणों को नि:शुल्क 10 हजार फलदार प्रजाति के पौधों का वितरण किया गया। साथ ही आधुनिक तकनीक ट्री-एटीएम के माध्यम से भी नागरिकों को सुगमता से पौधों का वितरण कर पौधारोपण के प्रति प्रोत्साहित किया गया। यह रथ पूरे जिले में व्यापक स्तर पर भ्रमण कर जन-जागरूकता अभियान चलाएगा।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवप्रवेशी बच्चों का किया आत्मीय स्वागत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उदयपुर में आयोजित विकासखंड स्तरीय 'शाला प्रवेश उत्सव' में सहभागिता कर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाकर नवीन शैक्षणिक जीवन की शुभ शुरुआत कराई तथा अध्ययन सामग्री भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं की।

इस अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और संस्कारित समाज के निर्माण की आधारशिला है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहां प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखारते हुए अपने सपनों को साकार कर सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने, नियमित विद्यालय आने तथा जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजेश अग्रवाल ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया और उनकी प्रतिभा की सराहना की। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवीन शैक्षणिक सत्र के अवसर पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकगण को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में परिवार और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पीएम सूर्य घर योजना से बस्तर के रघुचंद करें का बिजली बिल हुआ शून्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार भारी सब्सिडी और आसान किश्तों पर लोन देती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बस्तर के परिवारों के लिए आर्थिक राहत और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा माध्यम बनकर उभर रही है। इसका एक प्रेरक उदाहरण जिले के ग्राम तेलीमारेंगा निवासी हितग्राही रघुचंद कर्रे हैं। उन्होंने इस जनहितकारी योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया है, जिससे वे न केवल बिजली के बढ़ते खर्च से मुक्त हुए हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया है।

रघुचंद कर्रे ने बताया कि वे पूर्व से बिजली के सामान्य उपभोक्ता हैं। सोलर प्लांट लगने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1,500 रूपए आता था, जो हर महीने उनके परिवार के बजट पर एक अतिरिक्त बोझ साबित होता था। जब उन्हें इस योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत आवेदन कर इसका लाभ उठाया।

योजना के तहत उनके घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट की स्थापना के साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 8 हजार रुपए की भारी सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे उनके लिए यह संयंत्र लगाना बेहद आसान और किफायती हो गया।

सोलर संयंत्र शुरू होने के बाद अब रघुचंद के घर की अधिकांश बिजली की आवश्यकताएं इसी से पूरी हो रही हैं। सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त बिजली सीधे बिजली कंपनी (ग्रिड) को मिल रही है, जिसके चलते उनका मासिक बिजली बिल अब लगभग शून्य (0) हो गया है। श्री रघुचंद कर्रे ने कहा कि पहले हर महीने करीब डेढ़ हजार रुपए बिजली बिल देना पड़ता था, जिससे परिवार का बजट प्रभावित होता था। अब बिल शून्य हो गया है और हर महीने अच्छी बचत हो रही है। यह योजना हमारे जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

रघुचंद कर्रे ने आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य शासन के प्रति सहृदय आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बस्तर जिले के अन्य नागरिकों से भी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उनका कहना है कि यह योजना न केवल जेब पर पड़ने वाले भारी खर्च को रोकती है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और स्वच्छ-हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

जागरूकता से बीजापुर में बच्चों की सुरक्षा को मिली मजबूती

जिला बाल संरक्षण इकाई की सक्रियता से बाल यौन शोषण के मामलों में त्वरित कार्रवाई, दो मामलों में एफआईआर दर्ज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। चाइल्ड हेल्पलाइन1098 लाखों बच्चों के लिए आशा की किरण है। यह 24 घंटे, साल के 365 दिन चलने वाली एक नि:शुल्क आपातकालीन सेवा है, जो जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। हम न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए उन्हें उपयुक्त सेवाओं से भी जोड़ते हैं।

कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन में बीजापुर जिले में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा स्कूलों, ग्राम पंचायतों और विभिन्न समुदायों में नियमित रूप से किए जा रहे प्रचार-प्रसार से आम नागरिकों में सजगता बढ़ी है। इसी बढ़ती जागरूकता का परिणाम है कि अब लोग बाल अपराधों के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत होने वाले मामलों की जानकारी सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दे रहे हैं।

हाल ही में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त दो अलग-अलग शिकायतों पर जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की। टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ित बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उन्हें आवश्यक सुरक्षा, विशेषज्ञ परामर्श (काउंसलिंग) और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही दोनों ही मामलों में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की वैधानिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीड़ित बच्चों को शासन के नियमानुसार निर्धारित आर्थिक व सामाजिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे को एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। यदि किसी भी बच्चे के साथ शोषण या दुर्व्यवहार की घटना होती है, तो उसे शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रशासन हरसंभव सख्त कार्रवाई करता है। उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन एक 24 घंटे संचालित होने वाली पूरी तरह नि:शुल्क सेवा है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण, उत्पीड़न या संकट की स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गुप्त और गोपनीय रखा जाता है। बीजापुर जिला प्रशासन ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम या किसी बच्चे के लापता होने जैसी गंभीर घटनाओं को नजरअंदाज न करें। ऐसी किसी भी जानकारी या संदेह होने पर बिना किसी डर और देरी के तुरंत 1098 पर सूचित करें। समय पर दी गई एक छोटी सी सूचना संकट में फंसे बच्चों को सुरक्षित बचाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वन महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण का संदेश, मंत्री रामविचार नेताम ने किया रुद्राक्ष का पौधरोपण

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान बना जनभागीदारी का माध्यम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले के प्रयास आवासीय विद्यालय, भेलवाडीह में वनमंडल बलरामपुर द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान' के अंतर्गत वन महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिम जाति विकास तथा कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और नागरिकों से अधिकाधिक पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया।

मंत्री श्री रामविचार नेताम कार्यक्रम में 'एक पेड़ माँ के नाम प्रकृति संरक्षण का जन आंदोलन' के तहत आयोजित चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

मंत्री नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वन महोत्सव केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता का व्यापक अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रकृति के प्रति संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में वृक्षारोपण और वृक्षों का संरक्षण केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि आज प्रकृति की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है।

उन्होंने लोगों से प्रत्येक घर में पौधारोपण करने और हरित, स्वच्छ तथा पर्यावरण-अनुकूल समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सरकार उन्हें बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध करा रही है। इन अवसरों का लाभ उठाकर अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी से कम से कम एक पौधा लगाने, उसका संरक्षण करने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की विरासत को संरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने नागरिकों से अपने नाम तथा अपनी बेटी के नाम एक-एक पौधा लगाने की अपील करते हुए कहा कि जीवन के प्रत्येक चरण में वृक्षों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, मेहनत और निरंतर प्रयास के माध्यम से भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित किया तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, कैम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

सिल्क साड़ी में जाह्नवी कपूर ने बिखेरा जलवा

ट्रेडिशनल आउटफिट में लगाया बोल्डनेस का तड़का

बॉलीवुड की यंग और खूबसूरत एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इन लेटेस्ट तस्वीरों में जाह्नवी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने भारतीय परंपरा को बोल्डनेस के साथ पेश किया है। तस्वीरों में जाह्नवी कपूर ने एक बेहद खूबसूरत लैवेंडर और गोल्डन शेड वाली सिल्क साड़ी पहनी हुई है। साड़ी का बॉर्डर काफी हैवी है, जो इसे बेहद रॉयल लुक दे रहा है।

साड़ी के साथ जाह्नवी ने मैचिंग स्ट्रैपलेस स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके इस एथनिक लुक में मॉडर्न और ग्लैमरस टच जोड़ रहा है।

तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक सेक्सी और अट्रैक्टिव पोज देते नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। उनके इन बोल्ड पोज ने ट्रेडिशनल लुक में भी हॉटनेस का तड़का लगा दिया है।

जाह्नवी ने न्यूड-ग्लॉसी लिपस्टिक, सटल मेकअप, विंग्ड आईलाइनर और माथे पर एक छोटी सी बिंदी के साथ अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारा है।

इस रॉयल लुक को पूरा करने के लिए जाह्नवी ने अपने बालों का एक नीट और क्लीन स्लीक जूड़ा बनाया हुआ है, जिसे पारंपरिक हेयर एक्सेसरीज से सजाया गया है।

ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने गले में एक बेहद हैवी कुंदन और पर्ल का चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके, हाथों में ढेर सारी खूबसूरत चूड़ियां, बाजूबंद और अंगूठियां पहनी हुई हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

कई प्रोजेक्ट्स ठुकराने पर बोलीं अनुपमा की अद्रिजा रॉय

मैं इंतजार करना पसंद करूंगी, लेकिन बिना जुड़ाव के किरदार नहीं

अनुपमा में राही कपाडिया के किरदार से अभिनेत्री अद्रिजा रॉय ने घर-घर में पहचान बनाई है। अद्रिजा ने कहा कि वह वहीं किरदार निभाना पसंद करती है, जिससे उन्हें दिल से जुड़ाव महसूस होता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अब महिलाओं के लिए लिखे जाने वाले किरदारों में काफी सुधार आया है और दर्शक भी महिला केंद्रित कहानियों को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। अद्रिजा रॉय ने कहा, मुझे लगता है कि चीजें पहले से काफी बेहतर हुई हैं। अब महिलाओं को ज्यादा अहमियत रखने वाले किरदार मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दर्शक अब महिलाओं के नेतृत्व वाली कहानियों को स्वीकार कर रहे हैं। यह इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई किरदार लोकप्रिय हो जाता है तो लोग उसी तरह के रोल में कलाकार को देखने लगते हैं।

उन्होंने कहा, जब कोई भूमिका लोकप्रिय हो जाती है तो लोग आपको उसी अंदाज में देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उस किरदार को अच्छी तरह निभाया है। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देती। लेकिन एक कलाकार के तौर पर मैं हमेशा खुद को और दर्शकों को सरप्राइज करना चाहती हूं। मैं एक ही तरह के किरदार बार-बार नहीं करना चाहती। मेरे लिए हर नया रोल कुछ नया सीखने का मौका होना चाहिए।

अद्रिजा ने अपने करियर के फैसलों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, हर अभिनेता चाहता है कि उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हों, लेकिन यह इंडस्ट्री हमेशा इस तरह काम नहीं करती। कई बार कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस आपको ऐसा किरदार देता है, जो शायद आपकी पहली पसंद न हो। ऐसे में पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। कहानी क्या है, टीम कैसी है और किरदार शो में क्या योगदान दे रहा है, इन सभी चीजों को समझना जरूरी होता है। हर स्थिति में कोई एक सही या गलत जवाब नहीं होता। हर कलाकार को अपने हिसाब से फैसला लेना पड़ता है। बातचीत के दौरान अद्रिजा ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को मना किया है, जिनसे वह खुद को जोड़ नहीं पाईं।

उन्होंने कहा, हां, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मना किया है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे खराब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उन किरदारों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई। अगर मैं किसी भूमिका पर विश्वास नहीं करती हूं, तो मेरे लिए उसके साथ न्याय करना मुश्किल हो जाता है। मैं

इंतजार करना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसा काम करना चाहती हूं जो मुझे अंदर से उत्साहित करे।

बारिश और व्हाइट कपड़ों की दीवानी हैं मन्नत फेम आयशा सिंह

बोलीं- शूट के बाद भीगने चली गई

टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह इन दिनों अपने सीरियल मन्नत: हर खुशी पाने की को लेकर सुर्खियों में हैं। शो की कहानी, उनका किरदार और अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आता हैं। इसी बीच आयशा ने खुलासा किया कि उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जब भी मौका मिलता है, वो बारिश में भीगने चली जाती हैं। आयशा ने कहा कि शूट खत्म होते ही मैं बारिश में चली गई। मैंने टीम से पूछा कि क्या मैं भीग सकती हूं? उन्होंने कहा हां। फिर मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। बारिश की बूंदें एक अलग सुकून देती है। उनके इस बयान से लगता है कि वो इस मौसम को खुलकर जीती है और अपने दिन को एंजॉय करती हैं।

जहां बारिश में कई सेलेब्स को व्हाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद नहीं हैं क्योंकि भीगने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाते है। वहीं आयशा के ख्याल इससे बिल्कुल अलग हैं और उन्हें इस कलर से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे व्हाइट आउटफिट बहुत पसंद हैं। व्हाइट पे गो क्रेजी बारिश के साथ व्हाइट कपड़े का कॉम्बिनेशन कैमरे पर सबसे खूबसूरत लगता है। हालांकि आयशा को शॉर्ट्स, टी-शर्ट और फ्लिप-फ्लॉप वाला कैजुअल स्टाइल भी बहुत पसंद हैं।

वहीं बात करें सीरियल की, तो इसकी शुरुआत पिछले साल जनवरी में हुई, जो कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है। शो की कहानी मन्नत नाम की लड़की की है, जिसका सपना शेफ बनने का है। हालांकि उसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते है, जिससे उसकी जिंदगी बदलती हुई नजर आती है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानती और अपने परिवार के लिए खड़ी नजर आती हैं।

आदित्य रॉय कपूर की नई फिल्म का ऐलान, मिलाप मिलन जावेरी संग पहली बार करेंगे काम

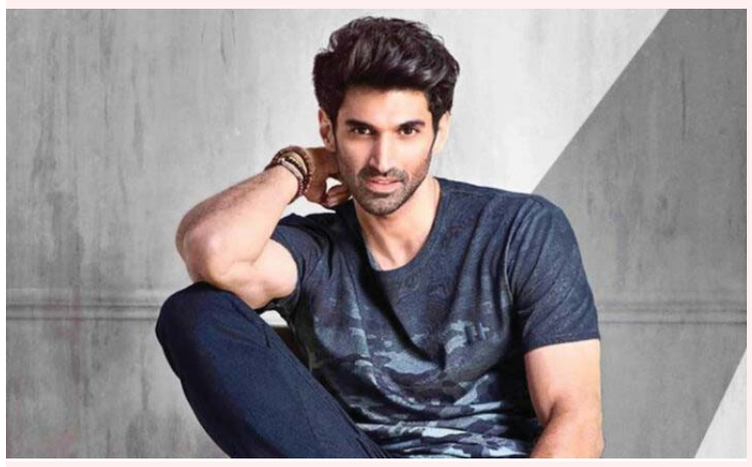

आशिकी 2, मलंग और मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्मों से अपनी रोमांटिक छवि बनाने वाले अभिनेता आदित्य रॉय कपूर अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर खास लव स्टोरी लेकर आने वाले हैं। इस बार वह पहली बार निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी के साथ हाथ मिला रहे हैं। दोनों की यह फिल्म रोमांस, एक्शन और संगीत का दमदार मेल होगी, जिसे निर्माता भूषण कुमार बड़े स्तर पर बना रहे हैं। निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी ने आदित्य रॉय कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, आदित्य प्यार को बेहद गहराई के साथ पर्दे पर उतारते हैं।

आशिकी 2 के बाद से दर्शकों ने उन्हें जुनून और टूटे दिल की कहानियों में खूब पसंद किया है। इस नई फिल्म का किरदार कई परतों वाला होगा। मुझे नहीं लगता कि इस सफर को उनसे बेहतर कोई और निभा सकता था।

वहीं, निर्माता भूषण कुमार ने आदित्य के साथ अपनी पुरानी साझेदारी को याद करते हुए कहा, आदित्य के साथ हमारा रिश्ता कई सालों पुराना है और हमने साथ मिलकर ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें दर्शक आज भी पसंद करते हैं। आशिकी 2 से लेकर मेट्रो इन दिनों तक हर फिल्म हमारे लिए खास रही है। हमारे बीच शानदार क्रिएटिव तालमेल है और मुझे खुशी है कि हम एक बार फिर एक ऐसी कहानी के लिए साथ आ रहे हैं, जो भावनात्मक और बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी।

फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर में शुरू होने की तैयारी है। इसके बाद पोस्ट-प्रोडक्शन का काम पूरा कर इसे साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल फिल्म की बाकी स्टारकास्ट और टाइटल का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन मेकर्स का कहना है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और जानकारियां साझा की जाएंगी।

फिल्म की घोषणा करते हुए मिलाप मिलन जावेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक खास पोस्ट साझा किया था। उन्होंने लिखा, इस बार आशिकी पूरी दीवानियत से होगी। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर रहा हूं। यह एक इंटेंस, हिंसक और म्यूजिकल लव स्टोरी है, जिसमें मेरे प्रिय मित्र और शानदार अभिनेता आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने आगे लिखा, आदित्य को उनके करियर के सबसे दमदार, रोमांटिक और हीरोइक किरदारों में से एक में देखने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे खुशी है कि यह फिल्म भूषण कुमार सर के बैनर तले बन रही है, जिनके साथ मैंने सत्यमेव जयते और मरजावां जैसी सफल फिल्मों में काम किया है।

उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, 2027 में सिनेमाघरों में मिलते हैं, जहां एक्शन, संगीत, दमदार डायलॉग, रोमांस, जुनून और दिल टूटने का दर्द- सब कुछ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा।

चॉकलेट के आदी बच्चों को खिलाएं उसके ये 5 सेहतमंद विकल्प, उन्हें स्वाद भी आएगा पसंद

बच्चों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन इसमें मौजूद चीनी और चर्बी के कारण उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में माता-पिता हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बच्चों को सेहतमंद मिठाइयां कैसे खिलाएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद विकल्प बताते हैं, जो चॉकलेट की तरह स्वादिष्ट हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। चॉकलेट के ये विकल्प सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट बच्चों के लिए एक बढिया विकल्प है। इसमें कम चीनी होती है और यह सेहत के लिए फायदेमंद तत्वों से भरी होती है। आप डार्क चॉकलेट को पिघलाकर मिल्कशेक या स्मूदी में मिला सकते हैं या इसे फल के साथ परोस सकते हैं। यह बच्चों को मिठास देने के साथ-साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखती है। डार्क चॉकलेट का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जिसे बच्चे इसे खुशी-खुशी खा लेंगे।

कैरब पाउडर

कैरब पाउडर कैरब फ्ल से बनता है और इसमें प्राकृतिक मिठास होती है। यह कोको पाउडर का सेहतमंद विकल्प है। आप इसे दूध, स्मूदी या दही में मिला सकते हैं या फिर इससे ब्राउनी और कुकीज बना सकते हैं। कैरब पाउडर में कैफीन नहीं होती, जिससे यह बच्चों के लिए सुरक्षित है। यह उनके लिए एक पौष्टिक विकल्प बन सकता है और उनकी सेहत का भी ख्याल रखता है। इसके अलावा यह स्वाद में भी बेहतरीन है।

मेपल सिरप

मेपल सिरप एक प्राकृतिक मीठा पदार्थ होता है, जिसे आप बच्चों के किसी भी व्यंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रिफाइंड चीनी का अच्छा विकल्प है और इसमें कई जरूरी तत्व होते हैं। आप इसे पैनकेक, वैफल्स या ओट्स पर डाल सकते हैं या फिर इसे स्मूदी में मिला सकते हैं। मेपल सिरप का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जिससे बच्चे इसे खुशी-खुशी खा लेंगे। यह उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

गुड़

गुड़ एक पारंपरिक मीठा पदार्थ है, जो आयरन और जरूरी तत्वों से भरा होता है। आप गुड़ को बारीक काटकर या कद्दूकस करके अपने बच्चों की रेसिपी में शामिल कर सकते हैं। गुड़ का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और खून साफ करता है। गुड़ का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जिससे बच्चे इसे खुशी-खुशी खा लेंगे। यह उनके लिए एक पौष्टिक विकल्प बन सकता है और उनकी सेहत का भी ख्याल रखता है।

फलों का सिरप

फलों का सिरप प्राकृतिक फलों से बनता है और इसमें कोई अप्राकृतिक स्वाद या रंग नहीं होता। आप इसे दही, आइसक्रीम या स्मूदी पर डाल सकते हैं या फिर इसे पानी में मिलाकर पी सकते हैं। फलों का सिरप बच्चों को ताजगी देता है और उनकी प्यास बुझाता है। इन सभी विकल्पों से न केवल बच्चों की मिठास की जरूरत पूरी होगी, बल्कि उनकी सेहत भी हमेशा बेहतर बनी रहेगी।

आकांक्षा चमोला को लेकर रुबिना दिलैक का नया खुलासा

बोलीं- उसे बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि.....

रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में आकांक्षा चमोला के दिए गए बयान और खुलासे इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने बच्चे न करने का फैसला लिया है। इस बात को लेकर एक्ट्रेस रुबिना ने भी एक बड़ी बात बोल दी है।

रुबिना दिलैक और आकांक्षा चमोला एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इनका कई बार मिलना भी हुआ। एक बातचीत में रुबिना को आकांक्षा ने कहा था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए उसका डॉग ही बच्चे जैसा है। यह बात सुनकर रुबिना थोड़ी चौंक गई थीं, क्योंकि वह उस वक्त गर्भवती थीं। रुबिना ने यह बातें अपने नए टॉक शो में कही हैं। इस टॉक शो में हिना खान भी नजर आ रही हैं। आकांक्षा के बारे में हुए इस खुलासे पर उन्होंने भी रिएक्शन दिया है।

रुबिना दिलैक और हिना खान ने आकांक्षा के नजरिए पर क्या कहा?

टॉक शो में रुबिना ने जब आकांक्षा चमोला का बच्चों को लेकर नजरिया बताया तो हिना खान ने कहा, 'हां, कई लोग बच्चों से ज्यादा प्यार डॉग्स से करते हैं। यह तो बहुत बड़ी डिबेट है।' इस पर हिना के पति रॉकी कहते हैं कि यह कोई बड़ी डिबेट नहीं है, इंसानी बच्चे की तुलना आप जानवर के बच्चे से नहीं कर सकते हो।' यही बात रुबिना के पति अभिनव भी कहते हैं।

हाल ही में टीवी सेलेब्स से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज पर रुबिना दिलैक और हिना खान ने एक नया टॉक शो शुरू किया। इसका नाम 'POV' है। इसमें रुबिना और हिना खान के पति भी शामिल होते हैं। इस शो में सबसे पहले इन चारों ने आकांक्षा चमोला को लेकर बातचीत की, क्योंकि इन दिनों वह कंट्रोवर्सी से घिरी हैं।

हिना खान और रुबिना का करियर फ्रंट?

हिना खान सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'कसौटी जिंदगी की 2' में नजर आई थीं। वहीं रुबिना दिलैक सीरियल 'छोटी बहू' और 'शक्ति अस्तित्व के अहसास की' में नजर आई थीं। ये दोनों एक्ट्रेसेस कई रियलिटी शो भी कर चुकी हैं।

बस्तर की जैविक खेती को मिलेगा वैश्विक बाजार : विजय शर्मा

नक्सल मुक्त गांवों की प्राकृतिक खेती बनेगी नई पहचान, एपीडा, कृषि एवं पंचायत विभाग के साथ बनी कार्ययोजना, बस्तर संभाग में होगा विशेष सर्वे और परीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़े बाजारों तक पहुंचाने तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन (मंत्रालय) में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बस्तर के उन गांवों की पहचान कर उनका जैविक प्रमाणन कराने के निर्देश दिए, जहां आज तक किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांव छत्तीसगढ़ की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं और इनकी जैविक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि हाल ही में नारायणपुर और कांकेर के नक्सल मुक्त हुए ग्रामों के अपने बस्तर प्रवास के दौरान अनेक किसानों ने उन्हें जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने खेतों में कभी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांवों को चिन्हित कर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) से जोड़ा जाए, ताकि उनके उत्पादों का विधिवत जैविक प्रमाणन कराया जा सके और उन्हें देश के बड़े बाजारों के साथ-साथ यूरोप सहित अन्य विदेशी बाजारों तक पहुंचाया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि जैविक प्रमाणन के बाद बस्तर के किसानों को उनके उत्पादों का वर्तमान मूल्य की तुलना में तीन से चार गुना अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बस्तर की विशिष्ट कृषि पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने एनपीओपी प्रमाणन के लिए आवश्यक तीन सालों की अवधि की आवश्यकता को बस्तर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए छूट देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वनोत्पादों को प्रमाणन की आवश्यकता ना होने से उसे भी एक्सपोर्ट रेडी करने के लिए तैयारी करने को कहा ताकि बस्तर के लोगों को वनोत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

उप मुख्यमंत्री ने जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ की प्रमाणन संस्थाओं की सेवाएं लेने तथा सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी कदम शीघ्र उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव श्री भीम सिंह, सचिव श्री धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन, एपीडा के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बस्तर के जिलों में जाएंगे संयुक्त दल, होगी टेस्टिंग

उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन के साथ दो संयुक्त दल गठित कर नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये दल एपीडा और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जैविक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे तथा जैविक उत्पादों के लिए आवश्यक परीक्षण और तकनीकी प्रक्रिया पूरी करेंगे। पूरे ग्राम पंचायतों को जैविक प्रमाणन दिलाकर बस्तर के उत्पादों को बिहान के छत्तीसकला ब्रांड द्वारा एक्सपोर्ट किया जाएगा।

यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए बनेगी रणनीति

बैठक में बस्तर के जैविक उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता, प्रमाणन और विपणन की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि बस्तर के उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके लिए ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों का निर्माण कर उत्पादन का हर किसी को भागीदार बनाया जाएगा।

खास खबर

प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना से बदली फूलमती देवी के परिवार की जिंदगी

रायपुर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के मठपारा निवासी फूलमती देवी का परिवार इसका प्रेरक उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पक्का मकान मिलने और महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनके परिवार के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और नई उम्मीद का संचार हुआ है। श्रीमती फूलमती देवी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि का उपयोग वे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं। परिवार का मुख्य आधार मेहनत-मजदूरी है, लेकिन सीमित आय के बावजूद वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके अनुसार यह सहायता राशि बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलना उनके परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। पहले वे कच्चे और छप्पर वाले मकान में रहते थे, जहां विशेषकर बरसात के मौसम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सुरक्षित और पक्के आवास में रहने से पूरे परिवार का जीवन अधिक सहज और सम्मानजनक हो गया है। फूलमती देवी के पति संजय चौधरी ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम से स्वीकृत आवास मिलने से परिवार की वर्षों पुरानी चिंता समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि पहले शौचालय और स्नानघर जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परिवार, विशेषकर महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

कौशल विकास से आत्मनिर्भर बनेंगे युवा: मंत्री रामविचार नेताम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कृषि एवं कृषक कल्याण तथा पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि बलरामपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को योजनाबद्ध ढंग से विकसित कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण तैयार कर युवाओं को गाइड, होम-स्टे, होटल प्रबंधन एवं अन्य पर्यटन सेवाओं से जोड़ने की प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक युवा को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर मिल सके।

मंत्री श्री नेताम शनिवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत राशि का उद्देश्यपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि उनका लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की साझा निगरानी से विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। मंत्री श्री नेताम ने किसानों एवं आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी सहकारी बैंकों में शेड तथा पर्याप्त बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री नेताम ने जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए तथा पिछले वर्ष स्वीकृत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें तथा जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की नियमित जानकारी उपलब्ध कराएं। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के महत्वपूर्ण कार्यों, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, डीएमएफ अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय तथा प्रमुख विकास गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास एवं आजीविका, स्वच्छता, कृषि, उद्यानिकी तथा पशुपालन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाएगा।

समय पर खाद-बीज और केसीसी से बदली सुकमा के किसानों की किस्मत

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप सुकमा जिला प्रशासन द्वारा खरीफ सीजन के मद्देनजर किसानों के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर अमित कुमार के कुशल मार्गदर्शन में जिले के सुदूर और वनांचल क्षेत्रों तक कृषि आदानों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके तहत किसानों को खेती शुरू होने से पहले ही खाद, उन्नत बीज और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋ ण समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें इस बार खरीफ की तैयारी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

शासन की इस समयबद्ध पहल का एक सीधा और सकारात्मक लाभ सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम नयागुड़ा निवासी किसान चनासू नाग को मिला है। आठ एकड़ कृषि भूमि के स्वामी नाग को कुकानार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से बेहद सुगमता से और सही समय पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण स्वीकृत कर दिया गया।

इसके साथ ही, उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश तथा उन्नत धान बीज भी आसानी से मिल गया। चनासू नाग ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि पहले के वर्षों में खेती का मौसम आते ही खाद, बीज और पैसों की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन जाता था। लेकिन इस बार सरकार की मुस्तैदी से सब कुछ समय पर मिल गया।

बच्चों में गैर-संचारी रोगों की समय पर पहचान के लिए विशेष अभियान, 200 से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जांच

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों की समय पर पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम बलरामपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग ने यूनिसेफएवं एमसीसीआर ट्रस्ट के सहयोग से विकासखंड शंकरगढ़ में बच्चों के लिए विशेष गैर-संचारी रोग स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया।

शिविर में 1 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 200 से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच के दौरान 7 बच्चे सिकल सेल रोग से प्रभावित पाए गए, जिन्हें आगे की विस्तृत जांच, परामर्श एवं उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर जांच और उपचार से सिकल सेल सहित अन्य गैर-संचारी रोगों की जटिलताओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सिकल सेल रोग, बाल मधुमेह तथा अन्य गैर-संचारी रोगों के लक्षण, नियमित जांच, समय पर उपचार और फॉलो-अप के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभिभावकों को सलाह दी गई कि यदि बच्चों में अत्यधिक कमजोरी, बार-बार बुखार, लगातार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन घटना या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तत्काल निकटतम स्वास्थ्य संस्थान में जांच कराएं। शिविर के दौरान बच्चों की समग्र स्वास्थ्य जांच, आवश्यक परामर्श तथा जरूरतमंद बच्चों के लिए उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ऐसे विशेष शिविरों के माध्यम से बच्चों में गैर-संचारी रोगों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

शिविर के सफल संचालन में स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ एमसीसीआर ट्रस्ट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम तथा विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारियों का सक्रिय सहयोग रहा।

श्वेत क्रांति की ओर बढ़ते धमतरी की महिलाओं के कदम

झारखंड के सफल डेयरी मॉडल का अध्ययन करने रवाना हुआ 43 महिला दुग्ध उत्पादकों का दल

आधुनिक तकनीक और सहकारी व्यवस्था सीखकर जिले में डेयरी विकास को देंगी नई दिशा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उत्पादक-स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं को वित्तपोषित करना और ऑपरेशन फ्लड जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

धमतरी जिले में महिला दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक डेयरी व्यवसाय को वैज्ञानिक व अधिक लाभकारी स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से जिले की 43 महिला दुग्ध उत्पादकों को एक विशेष अध्ययन भ्रमण पर झारखंड रवाना किया गया है। यह दल वहाँ के सफल डेयरी मॉडल, आधुनिक तकनीकों और कुशल सहकारी व्यवस्था का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेगा।

भ्रमण के दौरान धमतरी की महिला उद्यमी झारखंड में संचालित डेयरी विकास की विभिन्न कड़ियों को करीब से समझेंगी। प्रशिक्षण में वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन और उनके लिए संतुलित आहार प्रबंधन,?स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, दुग्ध संग्रहण एवं शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) प्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान,दूध के प्रसंस्करण से लेकर नए उत्पादों के निर्माण और उनकी विपणन व्यवस्था को समझना महिला डेयरी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (स्।त्रह्य) की सफल कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन आदि शामिल है।

आत्मविश्वास और आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यमरू कलेक्टर: महिला दुग्ध उत्पादकों के इस दल को रवाना करते हुए धमतरी कलेक्टर ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया।

उन्होंने कहा कि यह अध्ययन भ्रमण केवल एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि हमारी ग्रामीण महिलाओं के ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक प्रभावी प्रयास है। जब ये महिलाएं दूसरे राज्य के सफल मॉडलों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगी, तो वे अपने गांवों में भी इन नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगी। इससे जिले में दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और महिलाओं की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

जिले में सृजित होंगे स्वरोजगार के नए अवसर: कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि झारखंड से लौटने के बाद ये प्रतिभागी महिलाएं श्मास्टर ट्रेनरश् की भूमिका निभाएंगी। वे अपने अनुभवों और तकनीकी ज्ञान को जिले के अन्य दुग्ध उत्पादकों के साथ साझा करेंगी। ?जिला प्रशासन द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास धमतरी के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही ग्रामीण स्वरोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।

सीएम हेल्पलाइन बनी दिव्यांग प्रफुल्ल बेक के लिए उम्मीद की नई राह

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित सीएम हेल्पलाइन प्रदेश के जरूरतमंद नागरिकों के लिए भरोसेमंद सहारा बनकर उभर रही है। जशपुर जिले के बाबू सजबहार निवासी दिव्यांग प्रफुल्ल बेक की समस्या का त्वरित समाधान इसकी संवेदनशील और प्रभावी कार्यप्रणाली का प्रेरक उदाहरण है। प्रफुल्ल बेक चलने-फिरने में असमर्थ हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें गत वर्ष मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई थी, जिससे उनका दैनिक जीवन काफी आसान हो गया था। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पिछले चार माह से ट्राइसाइकिल बंद पड़ी थी। इससे उनका घर से बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया था।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

कृषि विभाग द्वारा बिना लाइसेंस उर्वरक तैयार करने पर की गई कार्रवाई

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में नकली, अवमानक तथा बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के उर्वरक एवं जैविक खाद का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग के उडऩदस्ता दल द्वारा डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम कातलवाही स्थित किसान मित्र स्वस्तिक ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में छापेमार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान संबंधित इकाई आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकी। छापेमारी के दौरान परिसर से विभिन्न प्रकार की उर्वरक एवं कच्ची सामग्री की कुल 2485 बोरी जब्त कर नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। जब्त सामग्री में प्रोम 1512 बोरी, बायोचार 62 बोरी, प्रिज्म चौंपियन 375 बोरी, पीवीसी एसजी 35 बोरी, सुपर ग्रेड-1 (ह्यूमेट 98 प्रतिशत) 14 बोरी, ह्यूमिक एसिड 19 बोरी, कंपोस्ट पाउडर 40 बोरी, व्हाइट क्ले (बेंटोनाइट) 40 बोरी, रॉक फॉस्फेट 40 बोरी, बायो एनपीके 8 बोरी तथा कुबेर बायो प्रोम 340 बोरी शामिल हैं।

रायपुर में मारपीट, चोरी और गांजा तस्करी के नए मामले दर्ज

रायपुर। रायपुर शहर में कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मामलों में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 10 नए अपराध दर्ज किए हैं। इनमें मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले शामिल हैं। कबीरनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। वहीं खम्हारडीह में एक नाबालिग के साथ केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए मारपीट करने का आरोप लगा है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में दोस्त द्वारा घर से 10 हजार रुपये चोरी करने का मामला सामने आया, जबकि पुरानी बस्ती में उधारी के विवाद को लेकर मारपीट और धमकी देने की शिकायत दर्ज हुई। टिकरापारा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 56 किलो 326 ग्राम गांजा जब्त किया है। पहली कार्रवाई में लालपुर ओवरब्रिज के पास स्कूटी से 46 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 24 लाख रुपये बताई गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में रावणभाठा बस स्टैंड के पास एक आरोपी सहित अन्य के कब्जे से 10 किलो 226 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 5.12 लाख रुपये आंकी गई है। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

बेमेतरा। शहर के वार्ड क्रमांक 17 स्थित नयापारा में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवक ने घर में पंखे से साड़ी के सहारे फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सिटी कोतवाली पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस की बड़ी सफलता : चोरी के 8 मामलों का खुलासा सोने-चांदी के जेवर सहित लाखों का सामान बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग पुलिस को चोरी के अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता मिली है। थाना पद्मनाभपुर व मोहन नगर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरियों के मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 168 ग्राम सोने के आभूषण, 150 ग्राम चांदी के आभूषण, 02 एलईडी टीवी, 01 डीवीआर, चोरी में प्रयुक्त उपकरण तथा दो चारपहिया एवं एक दोपहिया वाहन सहित लगभग 32 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया गया।

थाना मोहन नगर एवं थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में विगत कुछ समय से सूने मकानों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। लगातार हो रही इन घटनाओं को दुर्ग पुलिस द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। पुलिस टीमों द्वारा कई दिनों तक लगातार रात्रिकालीन पेट्रोलिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में सघन नाकेबंदी, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की निगरानी तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार फील्ड वर्क किया गया।

रात्रिगश्त में मिली संदिग्ध कार से पकड़ाए आरोपी

इस बीच शुक्रवार की रात को नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एक सफेद रंग की इंडिगो कार संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी। पुलिस ने कार रोककर उसमें सवार अनुराग मिश्रा निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जामुल तथा तुषार मिश्रा निवासी कैलाश नगर को अभिरक्षा में लिया गया। वाहन की तलाशी लेने पर 2 एलईडी टीवी, 1 डीवीआर, सब्बल, पेचकस एवं स्क्रूड्राइवर बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने थाना मोहन नगर एवं थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में हुई चोरी की अनेक घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।

लोन चुकाने शुरू की थी चोरियां

पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी अनुराग मिश्रा ने बताया कि वह वर्ष 2011 से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के रूप में कार्य करता था तथा प्रतिमाह लगभग 60,000 से ?70,000 तक आय अर्जित करता था। आरोपी के कथनानुसार बाद में उसने विभिन्न ऑनलाइन लोन एप्लीकेशनों से ऋण लिया। बढ़ते ब्याज एवं वित्तीय दायित्वों के कारण वह आर्थिक संकट में आ गया, जिसके बाद उसने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना प्रारंभ किया। पूछताछ में यह भी पता चला कि चोरी के अधिकांश सोने के आभूषणों को आरोपियों द्वारा विभिन्न फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखकर उसके एवज में राशि प्राप्त की गई थी। पुलिस संबंधित फाइनेंस कंपनियों से गिरवी रखे गए आभूषण बरामद किए गए।

रहवासी क्षेत्रों की अच्छी जानकारी

मुख्य आरोपी अनुराग मिश्रा पूर्व में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता था इसलिए उसे आवासीय क्षेत्रों की अच्छी जानकारी थी। उसे मकानों की सुरक्षा व्यवस्था एवं रहवासी क्षेत्रों की अच्छी जानकारी थी। आरोपी पहले सूने मकानों की रेकी करता था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मकान में कोई मौजूद नहीं है, रात्रि के समय सब्बल, पेचकस एवं अन्य उपकरणों की सहायता से मकान में प्रवेश कर सोने-चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं अन्य कीमती वस्तुओं की चोरी करता था।

फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखता था सामान

चोरी किए गए सोने के आभूषणों को आरोपी विभिन्न फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखकर उसके एवज में ऋण प्राप्त करता था तथा प्राप्त राशि का निवेश एवं व्यक्तिगत उपयोग करता था कुछ राशि अपने साथी के भी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया है , जिससे चोरी के सामान का तत्काल संदेह नहीं हो सके। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा मुथूट फाइनेंस (पावर हाउस), आईआईएफएल फाइनेंस (पावर हाउस), बजाज गोल्ड फाइनेंस (पावर हाउस) तथा मुथूट फाइनेंस (कुम्हारी) से वैधानिक प्रक्रिया के तहत गिरवी रखे गए आभूषण बरामद किए गए।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रमोद रुशिया, उप निरीक्षक मनोज बाजपेयी, आरक्षक आकाश, आरक्षक ओमप्रकाश, आरक्षक सर्वेश प्रजापति, आरक्षक जीत नारायण यादव, आरक्षक जमालुद्दीन, आरक्षक दिनेश राजपूत तथा रात्रिकालीन पेट्रोलिंग एवं नाकेबंदी में तैनात समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों को आश्वस्त करती है कि जनसुरक्षा एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में लगातार रात्रिकालीन गश्त, सघन नाकेबंदी, तकनीकी निगरानी एवं अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील है कि मकान सूना छोड़ने की स्थिति में स्थानीय पुलिस अथवा विश्वसनीय पड़ोसियों को अवश्य सूचित करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन अथवा गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। दुर्ग पुलिस अपराधों की रोकथाम, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा नागरिकों की सुरक्षा एवं संपत्ति की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर युवक से लाखो की ठगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी युवती ने पहले पीड़ित को वाट्सऐप ग्रूप से जोड़कर निवेश का झांसा दिया। शुरुआत में छोटा-छोटा मुनाफा दिखाकर उसका भरोसा जीता, फिर बड़ी रकम निवेश करवा ली।

जब पीड़ित विशाल गोयल ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने फोन बंद कर लिया। शिकायत के बाद खमतराई पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला खमतराई थाना इलाके का है।

खमतराई पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता विशाल गोयल ने बताया कि, 13 फरवरी 2026 को

अनिका शर्मा नाम की युवती ने वाट्सऐप के जरिए एक लिंक भेजा था। लिंक के माध्यम से उसे एक ट्रेडिंग ग्रूप से जोड़ा गया, जहां 30 दिन में निवेश की रकम दोगुनी करने का दावा किया जा रहा था। ग्रूप में लगातार मुनाफे के स्क्रीनशॉट और निवेश से होने वाले फायदे दिखाए जाते थे। शुरुआत में पीड़ित से कम राशि निवेश करवाई गई और उस पर लाभ दिखाकर उसका विश्वास जीत लिया गया। इसके बाद आरोपी ने अधिक मुनाफे का लालच देकर बड़ी रकम लगाने के लिए प्रेरित किया।

झांसे में आकर विशाल गोयल ने पांच अलग-अलग किश्तों में कुल 20 लाख रुपए बताए गए खातों में जमा कर दिए। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी जमा राशि और मुनाफा वापस मांगा तो आरोपी टालमटोल करने लगी।

खमतराई में पीड़ित ने दी शिकायत

अपने साथ ठगी होने का एहसास होने पर पीड़ित ने खमतराई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर बैंक खातों, मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि, सोशल मीडिया या वाट्सऐप ग्रूप के जरिए मिलने वाले निवेश के प्रस्तावों पर बिना जांच-पड़ताल भरोसा न करें। कम समय में रकम दोगुनी करने का दावा करने वाले ऑफर अक्सर साइबर ठगी का हिस्सा होते हैं।

शादीशुदा महिला ने दोस्तों से बॉयफ्रेंड को मरवाया

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शादीशुदा महिला ने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। महिला ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए घर बुलाया, जहां पहले से मौजूद कुछ युवकों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया। घायल अवस्था में उसे कुएं में फेंक दिया। किसी तरह इसकी जानकारी परिजनों को मिली।

तब युवक को कुएं से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक की पहचान दिलीप कडियम के रूप में हुई है। मामला मिरतुर थाना क्षेत्र का है। परिजनों के अनुसार, दिलीप का पिछले करीब एक साल से बीजापुर नगर पालिका में कार्यरत शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध था। दिलीप को बाद में महिला के विवाहित होने की जानकारी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना हुआ था।

परिजनों का आरोप है कि, 5 जुलाई को महिला ने दिलीप को शांतिनगर स्थित अपने घर बुलाया था। वहां पहले से कुछ युवक मौजूद थे। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद दिलीप पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि पहले उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया और फिर धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई गई।

घायल अवस्था में कुएं में फेंका

हमले के बाद घायल अवस्था में उसे कुएं में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल युवक को बाहर निकाला गया। उसे पहले बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल (मेकाज) रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

शव का पोस्टमॉर्टम किया गया

पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में परिजनों ने महिला और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

मैकेनिक ने सुसाइड से पहले पुलिसकर्मियों पर लगाए आरोप

रायपुर। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में मैकेनिक महेश दास मानिकपुरी की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। घटना के नौ दिन बाद मृतक के मोबाइल फोन से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने आत्महत्या से पहले एक पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने और वसूली का आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

खमतराई निवासी महेश दास मानिकपुरी ने 3 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद परिजनों ने उसका मोबाइल सुरक्षित रख लिया था। करीब नौ दिन बाद जब उन्होंने मोबाइल की जांच की, तो उसमें रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो मिला।

वीडियो में महेश ने पुलिसकर्मी बंटी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वह उसे लगातार परेशान कर रहा था और कथित रूप से वसूली के लिए दबाव बना रहा था। महेश ने वीडियो में अपनी मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया है।

वीडियो देखने के बाद परिजन पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते शिकायत पर ध्यान दिया जाता, तो शायद महेश की जान बच सकती थी। परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अधिकारियों ने जांच का दिया आश्वासन

खमतराई टीआई ने दैनिक भास्कर से चर्चा के दौरान बताया, कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर जांच की जा रही है। सुसाइड करने वाले महेश दास मानिकपुरी पर छह महीने पहले फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पैसे लेने के आरोप में कार्रवाई की गई थी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता, उसमें लगाए गए आरोपों और अन्य परिस्थितियों की बारीकी से जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई और मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच के दौरान सुरक्षा में मिली खामियां, समझाइश देने पर की अभद्रता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में होटलों की जांच के दौरान पुलिस टीम से अभद्रता करना होटल संचालक को महंगा पड़ गया। शहर के व्हाइट रोज होटल में औचक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में खामियां मिलने पर पुलिस ने संचालक को सुधार के निर्देश दिए।

लेकिन उसने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर जिलेभर के होटल, लॉज और गेस्ट हाउसों में सुरक्षा व्यवस्था और अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना साइबर

और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर स्थित व्हाइट रोज होटल में औचक जांच की।

निरीक्षण के दौरान होटल में सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई खामियां सामने आईं। इस पर पुलिस ने होटल संचालक सूरज सिंह (28) निवासी फतेहामुड़ा जूटमिल थाना क्षेत्र को आवश्यक सुधार करने की समझाइश दी।

पुलिस का कहना है कि, समझाइश के दौरान संचालक ने टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसका आक्रामक रवैया लगातार बना रहा। स्थिति को देखते हुए उसे कोतवाली थाना लाया गया, लेकिन वहां भी उसका व्यवहार नहीं बदला।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, कोर्ट में किया पेश

इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126 एवं 135(3) के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस ने बताया कि, जिले के होटल, लॉज और गेस्ट हाउसों की नियमित जांच जारी रहेगी। अभियान का उद्देश्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना, आगंतुकों का सत्यापन करना, अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गुंडागर्दी पर पुलिस का एक्शन, देर रात 30 जवानों ने की बाइक पेट्रोलिंग

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा में हाल ही में हुई मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं के बाद कोरबा पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शनिवार देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीएसपी और दोनों थाना प्रभारियों के नेतृत्व में 25 से 30 पुलिसकर्मियों ने संवेदनशील इलाकों में बाइक पेट्रोलिंग कर बदमाशों और उपद्रवियों को कड़ा संदेश दिया।

दो दिन पहले 15 ब्लॉक और पंप हाउस कॉलोनी में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। इसके बाद पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाते हुए शनिवार रात विशेष अभियान चलाया।

सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी, कोतवाली और सिविल लाइन थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पंप हाउस, 15 ब्लॉक, तुलसी नगर और डीडीएम रोड सहित कई इलाकों में बाइक से गश्त करते नजर आए। पुलिस उन संकरी गलियों तक भी पहुंची, जहां चार पहिया वाहन नहीं जा सकते।

उपद्रवियों के घर पहुंची पुलिस

पुलिस ने मारपीट और उपद्रव में शामिल युवकों की पहचान कर

उनके घरों पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवारों से युवाओं पर नजर रखने की अपील भी की गई।

शराब पीने और हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई

अभियान के दौरान देर रात सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे युवकों और बेवजह बाइक से घूमकर हुड़दंग मचा रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कई युवकों को रोककर समझाइश दी, जबकि कुछ से उठक-बैठक भी कराई गई।

पुलिस बोली- लगातार जारी रहेगा अभियान

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों से गुंडागर्दी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां विशेष रूप से बाइक पेट्रोलिंग कर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है।

रायपुर में विवाद के बाद चाकूबाजी ई-रिक्शा ड्राइवर समेत 3 लोग घायल

रायपुर। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को शहर के खम्हारडीह और सरोरा इलाके में ई-रिक्शा चालक समेत तीन लोग चाकू लगने से घायल हो गए। पहली घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र की है।

पुलिस के मुताबिक तेलीबांधा निवासी संजय निषाद गुरुवार शाम अपने साथी भरत यादव के साथ ई-रिक्शा से एक महिला यात्री को विशाल नगर से सेंट जेवियर्स स्कूल की ओर छोड़ने जा रहा था। सृष्टि प्लाजा, राजीव गांधी नगर के पास तीन युवकों ने रास्ते में गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की। इसी दौरान एक आरोपी ने संजय के सीने पर चाकू से वार करने की कोशिश की। संजय ने हाथ से वार रोक लिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने भरत यादव की कमर के ऊपर चाकू मार दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

घटना के बाद मौके से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें लगातार राहुल नाम से कॉल आ रही थी। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है।

लापरवाही से स्कूल वाहन चलाने वाला चालक गिरफ्तार

भिलाई। छावनी थाना क्षेत्र में स्कूल वाहन चालक की लापरवाही से एक चार वर्षीय बालक के घायल होने के मामले में पुलिस ने वाहन चालक हरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। करुणा हॉस्पिटल के पास नंदिनी रोड, भिलाई में घर छोड़ने के दौरान तेज गति और असावधानी से वाहन चलाने पर बालक नीचे गिर गया।

हादसे में उसके माथे, हाथ, पैर और दाहिने गाल पर चोटें आईं। बालक की माता ने उपचार के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 455/2026 के तहत बीएनएस की धारा 281, 125 और मोटरयान अधिनियम की धारा 184 में मामला की जांच शुरू की।

भोरमदेव में इको-टूरिज्म को मिली नई पहचान, उप मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव और 6 किमी लंबे इको ट्रेल का किया शुभारंभ

पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती- विजय शर्मा

- 51 काला आम के पौधों का हुआ रोपण, 50 हजार सीड बॉल और एक लाख पौधों के वितरण अभियान की हुई शुरुआत
- बैगा समुदाय के 100 हितग्राहियों को सोलर लालटेन और जैकेट का किया वितरण
- हर शनिवार और रविवार होगी इको ट्रेल, नेचर गाइड के साथ सुरक्षित वन भ्रमण की सुविधा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में प्रकृति संरक्षण और इको-टूरिज्म को नई पहचान देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जंगल सफारी में वन महोत्सव और भोरमदेव इको ट्रेल का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ लगभग 6 किलोमीटर लंबी भोरमदेव इको ट्रेल का भ्रमण कर जंगल की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और रोमांचक वन यात्रा का अनुभव लिया।

प्राकृतिक पर्यावरण में की जाने वाली एक जिम्मेदार यात्रा है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वहां के प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों का संरक्षण करना, और स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाना है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू होने के बाद पर्यटक अब जंगल के अंदर जाकर प्रकृति का करीब से आनंद ले रहे हैं। अब आज से शुरू हुई भोरमदेव इको ट्रेल भी पर्यटकों को घने जंगल, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के बीच एक नया और यादगार अनुभव देगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने भोरमदेव क्षेत्र को अनमोल प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध किया है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। भोरमदेव में पर्यटन सुविधाओं के बढ़ने से यहां अधिक पर्यटक आएंगे। इससे होटल, वाहन, खान-पान, हस्तशिल्प और अन्य छोटे-बड़े व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। अभी भी कई युवा जंगल सफारी में नेचर गाइड बनकर पर्यटकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे अवसर और बढ़ेंगे, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि साल भर यहां पर्यटन गतिविधियां तेजी से चलने की संभावना है, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि भोरमदेव का विकास तभी सफल होगा, जब स्थानीय लोग इसे अपनी धरोहर मानकर इसकी सुरक्षा करेंगे। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इस प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

वन महोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने करिया आमा ग्राम में 51 काला आम के पौधों का रोपण कर काला आम उपवन की स्थापना की। इसके साथ ही जिलेभर में 50 हजार सीड बॉल रोपण अभियान का शुभारंभ किया। जिले में एक लाख पौधों के वितरण अभियान की शुरुआत करते हुए ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में बैगा समुदाय के 100 हितग्राहियों को सोलर लालटेन और जैकेट भी वितरित की गई।

स्वदेश दर्शन योजना से बदलेगी भोरमदेव की तस्वीर

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भोरमदेव क्षेत्र के समग्र पर्यटन विकास के लिए 146 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रवेश द्वार, शेड, संग्रहालय, आधुनिक पार्क, पार्किंग, मेला स्थल, छेरकी महल, मड़वा महल, रामचूंआ और सरोदा बांध सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।

6 किलोमीटर लंबी इको ट्रेल में मिलेगा प्रकृति के बीच रोमांच

वन विभाग द्वारा विकसित भोरमदेव इको ट्रेल लगभग 6 किलोमीटर लंबी है, जिसे पूरा करने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ट्रेल के दौरान पर्यटक प्राकृतिक वन, मनमोहक दृश्य, पक्षियों और तितलियों का अवलोकन, औषधीय वनस्पतियों की जानकारी तथा प्रशिक्षित नेचर गाइड के साथ सुरक्षित वन भ्रमण का आनंद ले सकेंगे।

भोरमदेव ईको ट्रेल हर शनिवार और रविवार को होगी आयोजित

भोरमदेव ईको ट्रेल का संचालन करियाआमा गेट स्थित भोरमदेव ईको कैंप से प्रत्येक शनिवार और रविवार को किया जाएगा। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि अनुभवी नेचर गाइड के साथ प्रतिभागियों को जंगल भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान वे पेड़-पौधों, औषधीय वनस्पतियों, पक्षियों, तितलियों, वन्यजीवों, स्थानीय भोजन, भोरमदेव मंदिर विरासत परिसर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईको ट्रेल में भाग लेने के लिए 1 हजार रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है।

पंचायत के कार्यों में गुणवत्ता हो सर्वोच्च प्राथमिकता - विजय शर्मा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कमर कसकर अगले आठ महीनों में निर्धारित सभी लक्ष्यों को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में वीबी जीरामजी योजना एवं पंचायत विभाग के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) से जुड़े।

उप मुख्यमंत्री ने सभी जिला पंचायत सीईओ को अपने-अपने विकासखंडों का नियमित भ्रमण करने, निर्माण कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता और जवाबदेही आवश्यक है।

हर स्कूल में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण के निर्देश

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत संतृप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्रामों में मुक्तिधाम उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मुक्तिधाम निर्माण कराने तथा अनुपयोगी एवं खराब पड़े बोरवेलों को इंजेक्शन वेल के रूप में विकसित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

वीबी जीरामजी योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने तथा सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीबी जीरामजी योजना का लाभ तेजी से प्रत्येक ग्राम तक पहुंचना चाहिए। मंत्री श्री शर्मा ने वीबी जीरामजी के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएम श्री विद्यालयों, पोटा केबिनों एवं अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण एवं शौचालय निर्माण, धरसा विकास जैसे जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए श्री शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों की समयबद्ध जियो-टैगिंग कराने तथा नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीब परिवारों के आवास निर्माण में यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने सभी जिला पंचायत भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए जिन जिला पंचायतों में सौर ऊर्जा स्थापनाएं नहीं है वहां स्थापना करवाने तथा एनआरएलएम की दीदियों को प्रशिक्षित कर कार्य प्रदान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक एनआरएलएम अश्वनी देवांगन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बस्तर गोंचा महापर्व 2026 का निमंत्रण लेकर मुख्यमंत्री साय से मिले प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री ने तुपकी चलाकर दी भगवान श्री जगन्नाथ को प्रतीकात्मक सलामी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में बस्तर गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गोंचा महापर्व-2026 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए महापर्व के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ को पारंपरिक रूप से दी जाने वाली सलामी तुपकी चलाकर महापर्व की सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान किया।

प्रतिनिधिमंडल ने जगदलपुर शहर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड किए जाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे शहर में विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान हुआ है तथा भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के सुचारु संचालन में आने वाली बाधाएँ भी समाप्त हो गई हैं।

360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश पाण्डे ने बताया कि समाज अपनी 619 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व का आयोजन कर रहा है। भगवान श्री 1008 जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथयात्रा 16 जुलाई को श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सिरहासार भवन में संपन्न होगी, जहाँ महाप्रभु विराजमान होंगे।

इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष मुक्तेश पाण्डे सहित समिति के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से किसानों को मिली राहत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावा राशि प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने संबंधित बीमा कंपनी के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र किसानों को उनकी स्वीकृत दावा राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के दौरान प्रत्येक प्रकरण की गंभीरतापूर्वक जांच की गई। आवश्यक दस्तावेजों एवं अभिलेखों के सत्यापन के

उपरांत विकासखंड छुईखदान के ग्राम चोभर निवासी कृषक हरी पटेल को 4,283 रूपए ग्राम सलौनी निवासी दुलरवा वर्मा को 58,623 रूपए तथा विकासखंड खैरागढ़ के ग्राम चारभाठा निवासी धनसिंह को 21,039 रूपए की दावा राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। दावा राशि प्राप्त होने से किसानों को आर्थिक राहत मिली है। जिला प्रशासन ने बताया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा संबंधित विभागों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम तथा अन्य कारणों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। शिकायतों के त्वरित निराकरण से किसानों का शासन की योजनाओं के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है तथा उन्हें समय पर राहत उपलब्ध हो रही है।

स्वामित्व योजना का बड़ा कदम- 62 गांवों के नक्शे और संपत्ति विवरण जारी

रायपुर। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों की आवासीय भूमि की मैपिंग कर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक निर्धारण की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है। कुल 501 राजस्व गांवों में आधुनिक ड्रोन तकनीक से सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कार्यान्वयन एजेंसी सर्वे ऑफइंडिया द्वारा प्रथम चरण में 62 गांवों के अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ई-मालखाना का किया शुभारंभ

नवीन बस सहित चार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कांकेर सिटी कोतवाली थाने में ई-मालखाना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर जिला पुलिस को प्राप्त एक नवीन बस सहित चार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

कांकेर सिटी कोतवाली में स्थापित ई-मालखाना क्यूआर कोड आधारित प्रदेश का पहला थाना है, जहां डिजिटल ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थित ढंग से सरलीकृत किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ई-मालखाना के शुभारंभ के बाद जब्तशुदा सामानों की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने जिला पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे बेहतर व्यवस्था बताया।

उप मुख्यमंत्री को पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि ई-मालखाना प्रणाली एक आधुनिक डिजिटल प्रबंधन व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अपराध के दौरान विभिन्न प्रकरणों में जब्त की गई संपत्तियों एवं दस्तावेजों का सुरक्षित, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस प्रणाली का उद्देश्य जब्त संपत्ति के रखरखाव को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं जवाबदेह बनाना है, ताकि विवेचना एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सामग्री को शीघ्रता से खोजकर प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि ई-मालखाना में जब्त किए गए वाहन, मोबाइल फोन, नकदी, हथियार, आभूषण, एनडीपीएस प्रकरणों से संबंधित सामग्री तथा अन्य केस प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे प्रत्येक वस्तु का सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित डेटा उपलब्ध रहता है।

उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस कांकेर द्वारा अपराध के दौरान जब्तशुदा हथियारों, उपकरणों व सामानों के रखरखाव की प्रबंधन प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिकीकृत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई-मालखाना शुरू किया गया है, जिसमें संपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रत्येक बॉक्स के लिए क्यूआर कोड जनरेट किया गया है। बॉक्स में चस्पा क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अपराध प्रकरण का विवरण, बॉक्स में बंद जब्त सामान की जानकारी संख्या और तिथि सहित मिल जाती है।

साथ ही जब्त सामान या उपकरण जैसे मोबाइल, नकदी, हथियार, आभूषण, मादक द्रव्य, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आदि का डिजिटल रिकॉर्ड क्यूआर कोड की स्कैनिंग से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे डिजिटल अभिलेख और पेपरलेस वर्क भी आसान तरीके से मुहैया हो जाएगा।

प्रदेश में क्यूआर कोड के जरिए मालखाने के डिजिटाइजेशन का कार्य कांकेर पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के थानों में अब तक बार कोड स्कैनर की सुविधा थी, लेकिन क्यूआर कोड से डिजिटल मालखाना प्रबंधन प्रणाली पहली बार लागू की गई है। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सांसद भोजराज नाग, विधायक आशाराम नेताम, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी तथा कांकेर नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण कौशिक, उपाध्यक्ष उत्तम यादव, सतीश लाटिया, महेश जैन, आलोक ठाकुर, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले, एएसपी आकाश श्रीमाल और जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी सहित गृह विभाग के अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

राज्य सरकार महिलाओं को खेल सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरतः रामविचार नेताम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश में महिलाओं की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और खेल संस्कृति को मजबूत बनाने की दिशा में बलरामपुर जिले में आयोजित 'खेलेगा बलरामपुर, बढ़ेगा बलरामपुर' अभियान के तहत महिला खेल-कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। विकासखंड बलरामपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न गांवों से पहुंची महिला प्रतिभागियों ने 100 एवं 200 मीटर दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, खो-खो, कबड्डी और रस्साकशी जैसी स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को खेल सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन का आधार हैं। निरंतर अभ्यास और समर्पण से खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं। मंत्री नेताम ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उन्हें भविष्य में भी खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के समापन पर विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, शील्ड, मेडल एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

आयोजन की विशेष पहल के रूप में महिला प्रतिभागियों को एक-एक पौधा वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। प्रतिभागियों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने तथा पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया गया, जिससे खेल के साथ सामाजिक सरोकारों को भी बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हिरामुनी निकुंज, रेडक्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कृष्णा गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षपुष्पा नेताम, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950